दैनिक राष्ट्रीय गरिमा

राष्ट्र भक्ति की अलख जगाता

www.rashtriyagarima.com

राष्ट्र एक बगीचा है और हम सब इसके माली

■ भोपाल, मंगलवार 03 नवम्बर 2026 ■ पृष्ठ : 8, मूल्य ₹ 2 ■ वर्ष : 31, अंक : 138 ■ RNI No.61858/95 ■ Email- rgarima2005@gmail.com



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल से सौजन्य भेंट की।

सुविचार

जो लोग गिरकर भी उठते हैं, उन्हें ही सफलता मिलती है।

खातेगांव में अवैध शराब पकड़ने गये टीआई को कुचलकर मार डाला

गुजरात से आयशर वाहन में अवैध शराब आने की मिली थी थाने को खबर

देवास घटना में लापरवाही पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी निलंबित



भोपाल। देवास जिले के खातेगांव में अवैध मदिरा परिवहन से जुड़ी गंभीर घटना के मामले में आबकारी विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए हरदा जिले के टिमरनी वृत्त में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी अमर सिंह वघेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई प्रथम दृष्टया कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं निगरानी में शिथिलता पाए जाने पर की गई है। सहायक आबकारी आयुक्त, जिला देवास से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार रविवार देर रात्रि के दौरान अवैध मदिरा परिवहन की सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक क्रमांक एमपी-43 एच-4786 से थाना प्रभारी, खातेगांव के साथ गंभीर घटना घटित हुई। मौके पर ट्रक की जांच में गुप्त चैम्बर में छिपाकर रखी गई बैगपाइपर मदिरा पाई गई। यह मदिरा हरदा जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान हरदा रोड, टिमरनी एवं कम्पोजिट मदिरा दुकान सोडलपुर रोड, टिमरनी को प्रदाय होना पाया गया। प्रकरण की जांच में प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि संबंधित क्षेत्र में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी अमर सिंह वघेल द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में सतत निरीक्षण एवं प्रभावी निगरानी नहीं की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्री वघेल को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय उपायुक्त आबकारी कार्यालय, संभागीय उड़नदस्ता,भोपाल निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

प्रमुख संवाददाता

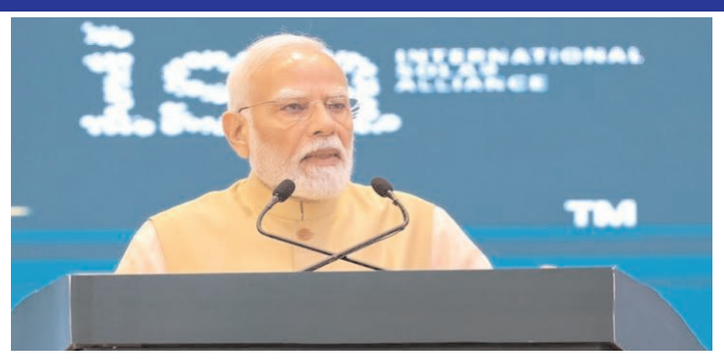
देवास। मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान रविवार देर रात को दर्दनाक घटना सामने आई है। इंदौर-बैतूल हाईवे पर शराब से भरे आयशर वाहन ने खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी को कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल टीआई को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया,जहां करीब दो घंटे तक सीपीआर और उपचार के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। सोमवार तड़के उनकी मौत की खबर से पुलिस महकमे में शोक छा गया। जानकारी के अनुसार, रविवार देर रात करीब डेढ़ बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि हरदा की ओर से अवैध शराब से भरा एक आयशर वाहन गुजरात की तरफ जा रहा है। इसके बाद देवास एसपी आदित्य मिश्रा के निर्देश पर वाहन को पकड़ने के लिए पुलिस की पांच से अधिक टीमें बनाई गई थीं। इनमें खातेगांव, नेमावर, कन्नौद और सतवास थाना क्षेत्रों की पुलिस टीमें शामिल थीं। पुलिस वाहन का पीछा कर रही थी और आगे भी नाकाबंदी की गई थी। इसी दौरान इंदौर-बैतूल हाईवे पर डिवाइडर के किनारे आयशर वाहन खड़ा मिला। बताया गया कि चालक पानी पीने के लिए रुका था। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी दिलीप पुरी ने चालक को वाहन से नीचे उतरने के लिए कहा। इसी दौरान चालक ने वाहन को डिवाइडर पर चढ़ाकर आगे बढ़ाने की कोशिश की। इस दौरान टीआई पुरी वाहन की चपेट में आ गए और पिछला पहिया उनके ऊपर से गुजर गया। हादसे में पुरी को शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने करीब दो घंटे तक सीपीआर सहित अन्य उपचार किए, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना के बाद आयशर चालक वाहन को डिवाइडर पर चढ़ाकर आगे ले गया और संदलपुर के पास छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। वाहन में शराब भरी होने की पुष्टि पुलिस अधिकारियों ने की है। शराब की मात्रा और तस्करी से जुड़े नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है।

होशियारपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर अरोड़ा के घर ईडी की दबिश

होशियारपुर। पंजाब के होशियारपुर में सोमवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता सुंदर शाम अरोड़ा के आवास पर छापेमारी की। सुबह करीब पांच बजे तीन गाड़ियों में पहुंचे ईडी के अधिकारी जोधा मल रोड स्थित उनके आवास में दाखिल हुए। कार्रवाई की सूचना फैलते ही इलाके में हलचल मच गई। जानकारी के मुताबिक, ईडी की टीम ने सुबह-सुबह अरोड़ा के घर पहुंचकर जांच शुरू की। इस दौरान आवास के आसपास सुरक्षा जवानों की तैनाती कर दी गई और पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के समय सुंदर शाम अरोड़ा भी अपने आवास पर मौजूद थे। फिलहाल ईडी की इस कार्रवाई के पीछे किस मामले की जांच की जा रही है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अधिकारियों की ओर से भी छापेमारी के उद्देश्य या जांच से जुड़े किसी मामले को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। ईडी की टीम की कार्रवाई जारी रहने के बीच इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि, जांच के कारणों और कार्रवाई के मकसद की पुष्टि आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही हो सकेगी।

500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता जोड़ने का प्रयास करेगा भारत : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन प्रदर्शनी का किया उद्घाटन



नई दिल्ली,(एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत अगले 10-11 वर्षों में 500 गीगावाट अतिरिक्त गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता जोड़ने का प्रयास करेगा। इससे इस दशक के अंत तक देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश अवसर पैदा होंगे। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में भारत नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में कहा कि भारत में राजनीतिक और नीतिगत स्थिरता के साथ-साथ बड़े पैमाने पर मांग और विकास की संभावनाएं हैं, जो इसे वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों की है और देश करीब 300 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल कर चुका है। भारत सौर और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष तीन देशों में शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 2021 के सम्मेलन में 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने का संकल्प लिया था। पेरिस समझौते के तहत कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य भी भारत ने 2025 में ही हासिल कर लिया, जो निर्धारित समय से पांच साल पहले है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी और पश्चिम एशिया संकट सहित पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने कई बड़े आर्थिक संकटों का सामना किया है। पश्चिम एशिया का संकट अभी भी जारी है, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों ने इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया है और देश की विकास दर ऊंची बनी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि भारत ने पिछले एक दशक में स्वच्छ ऊर्जा में निवेश नहीं किया होता और इसके लिए नई व्यवस्थाएं विकसित नहीं की होतीं, तो इन वैश्विक संकटों का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर कहीं अधिक गंभीर हो सकता था। इन संकटों ने स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा सीधे आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा का आधार स्वच्छ ऊर्जा ही है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वादों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2021 में भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले 10-11 वर्षों में 500 गीगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर सरकारी भवन, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सड़क प्रकाश व्यवस्था को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। देश में 44 हजार से अधिक सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जा चुका है, जिससे हर साल करीब 700 करोड़ रुपये की बचत हो रही है। उन्होंने फरवरी 2024 में शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत एक करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगाने का लक्ष्य है।

विपक्ष जीतता है तो लोकतंत्र सुरक्षित, हारते ही आ जाता है खतरे में : नितिन नवीन



भागलपुर,(एजेंसी)। बिहार के भागलपुर में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान नितिन नवीन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए उसके दोहरे रवैये पर सवाल उठाए। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष जब चुनाव जीतता है तो उसे लोकतंत्र पूरी तरह सुरक्षित नजर आता है, लेकिन जनता से चुनाव में हार मिलने के बाद वही लोकतंत्र को खतरे में बताने लगता है। उन्होंने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उसने समय रहते अपनी मानसिकता नहीं बदली, तो आने वाले दिनों में जनता उसकी बची-खुची राजनीतिक जमीन भी छीन लेगी। इससे पहले सोमवार सुबह विशेष विमान से भागलपुर हवाई अड्डा पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने नितिन नवीन का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद लाजपत पार्क स्थित सभा स्थल और पदयात्रा मार्ग पर राजग कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी। इस अवसर पर उत्साहित कार्यकर्ताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को विशाल त्रिशूल भेंट कर सम्मानित किया। पदयात्रा में भाजपा के साथ-साथ राजग के विभिन्न घटक दलों के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए। यात्रा का नेतृत्व करने से पहले मीडिया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित विपक्ष की रैली पर निशाना साधा। उन्होंने कहा,कल दिल्ली में विपक्ष के साथी केवल झूठ की खेती करते नजर आ रहे थे। उनके नेता राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार से ही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की शुरुआत हुई थी। जब विपक्ष कर्नाटक में चुनाव जीतता है तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन बिहार में हार मिलने के बाद ईवीएम और वोट चोरी के आरोप लगाने लगता है। उन्होंने राहुल गांधी पर विदेशों में जाकर देश के लोकतंत्र,चुनाव आयोग और उच्चतम न्यायालय का अपमान करने का आरोप भी लगाया। राजनीतिक विरोधियों की ओर से उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए नितिन नवीन ने कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि जब देश के 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी उसकी सत्ता है, तो फिर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा,लोकतंत्र की रक्षा करना और देश की जनता के भरोसे को बनाए रखना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। विपक्ष देश में झूठ,भ्रम और अराजकता का माहौल पैदा करने की जो कोशिश कर रहा है,उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पदयात्रा में राजग के कई प्रमुख नेता भी शामिल हुए। नितिन नवीन के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी,बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री दिलीप जायसवाल, नीतीश मिश्रा, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश और मंत्री संतोष सुमन ने भी पदयात्रा में हिस्सा लिया। इसके अलावा भागलपुर के नगर विधायक रोहित पांडे, भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार, नवगछिया जिलाध्यक्ष मुक्तिनाथ निषाद, जिला प्रभारी राजेश जैन, भाजपा महामंत्री योगेश पांडे और कार्यक्रम संयोजक नितेश सिंह समेत राजग के कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी सभा और पदयात्रा में मौजूद रहे।

एनसीपी नेता शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, रूबी अस्पताल में भर्ती

पुणे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के वरिष्ठ नेता शरद पवार की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों की सलाह पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें खांसी और कमजोर की शिकायत थी। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। शरद पवार ने शनिवार, 31 अक्टूबर और रविवार, 01 नवंबर को सोलापुर जिले के माढा तालुका स्थित तुलशी गांव और पंढरपुर तालुका के दुधाली गांव का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने तुलशी गांव में सूखे की स्थिति का जायजा लिया और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने किसानों की समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाने का आश्वासन भी दिया था। हालांकि,सोमवार को प्रस्तावित शरद पवार का सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा रद्द कर दिया गया था। पहले मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को दौरा रद्द होने की वजह बताया गया था। हालांकि,अब बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब होने के कारण यह दौरा रद्द किया गया था। इसके बाद पवार सोलापुर से पुणे पहुंचे, जहां तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सीएम उमर और निधि की शादी पर मौलना रजवी ने जारी किया फतवा

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और वरिष्ठ पत्रकार निधि राजदान के विवाह को लेकर धार्मिक गलियारों में विवाद खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस शादी के खिलाफ फतवा जारी करते हुए इसे इस्लामी शरीयत की कसौटी पर पूरी तरह गैर-कानूनी और नाजायज करार दिया है। मौलाना के इस कड़े रुख और फतवे के सामने आने के बाद राजनीतिक व सामाजिक स्तर पर नई बहस छिड़ गई है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने रविवार को अपने बयान में कहा कि इस्लाम में निकाह को लेकर बेहद स्पष्ट और निर्धारित कायदे-कानून बनाए गए हैं। शरीयत के अनुसार एक मुस्लिम पुरुष और गैर-मुस्लिम महिला के विवाह को लेकर सख्त प्रावधान तय हैं। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि उमर अब्दुल्ला मुस्लिम हैं और निधि राजदान गैर-मुस्लिम हैं, इसलिए इस्लामी नजरिए से यह निकाह मान्य नहीं ठहरता। मौलाना ने कहा कि यदि विवाह से पहले निधि राजदान का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें इस्लाम कबूल कराया जाता और उसके बाद निकाह होता, तभी यह रिश्ता इस्लामी नियमों के तहत जायज माना जा सकता था। धार्मिक नियमों की अनदेखी के चलते इस निकाह को शरीयत से खारिज किया जाता है।

भारत के गौरवशाली अतीत से परिचय कराना वीर भारत न्यास का उद्देश्य : मुख्यमंत्री यादव



मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई वीर भारत न्यास कार्यसमिति की बैठक

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्राचीनतम से आधुनिक इतिहास के मुख्य आयामों और भारत का राष्ट्र स्वरूप स्थापित करने में अपना योगदान देने वाले चिंतकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों से जुड़ी गतिविधियों और देश-प्रदेश की संस्कृति पर कार्य के लिए वीर भारत फैलोशिप प्रदान की जाएगी। प्रतिवर्ष दो फैलोशिप प्रदान की जाएंगी, फैलोशिप की राशि 12 लाख रुपए प्रति अध्येता होगी, यह फैलोशिप एक वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी। बैतूल में केन्द्र सरकार के सहयोग से आरण्यक युगयुगीन जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। जिसमें जनजातीय इतिहास गैलरी, जनजातीय स्वाधीनता आंदोलन, जनजातीय शोध केन्द्र और डिजीटल रिपॉजिटरी स्थापित होंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस आश्रय के प्रस्ताव को वीर भारत न्यास की कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदित किया। बैठक में भारतीय इतिहास, संस्कृति और वैभवपूर्ण विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उज्जैन कोठी महल में स्थापित हो रहे वीर भारत संग्रहालय के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई। मंत्रालय में हुई इस बैठक में संस्कृति राज्य मंत्री श्री धमेन्द्र भावसिंह लोधी वर्चुअली शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि केवल युद्धों और योद्धाओं की कथा मात्र नहीं अपितु भारत की आंतरिक शक्ति,उसके सोचने-एकजुट होने-प्रश्न करने,रक्षा और त्याग करने तथा सृजन के सामर्थ्य से विश्व को अवगत कराना आवश्यक है। उज्जैन में स्थापित होने वाला वीर भारत संग्राहलय इस केन्द्रीय भाव को प्रतिपादित करेगा कि भारत के इतिहास में वीरता का अर्थ कभी केवल युद्ध के साहस तक सीमित नहीं रहा। संग्रहालय, योद्धा के साथ-साथ ऋषि, शिक्षक,गणितज्ञ, समाज सुधारक, विधि निर्माता और तीर्थ यात्रियों को भी प्रदर्शित करेगा। भारत के गौरवशाली और पराक्रमी अतीत से जनसामान्य का परिचय कराना वीर भारत न्यास का उद्देश्य है। बैठक में बताया गया कि न्यास द्वारा वर्ष 2024 से निरंतर सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्य, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय चेतना से संबंधित गतिविधियां आयोजित की गई। भोपाल में सदानीरा समागम, महाभारत समागम तथा उज्जैन में श्री महाकालेश्वर महोत्सव आयोजित किए गए। बैठक में न्यास द्वारा संचालित फिल्म समारोह, सांगीतिक प्रस्तुतियों और सोशल मीडिया संबंधित गतिविधियों की जानकारी भी दी गई। बैठक में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई,मनीष रस्तोगी, शिवशेखर शुक्ला तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

राजधानी भोपाल में एक ही परिवार के पांच सदस्यों के शव मिले

छोला का मामला,हत्या की आशंका, रेलवे ट्रैक पर मिला मुखिया का शव



भोपाल। राजधानी भोपाल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। छोला थाना क्षेत्र के ग्राम मालीखेड़ी में सोमवार सुबह एक घर में परिवार के चार सदस्यों के शव मिले हैं। वहीं एक व्यक्ति (परिवार के मुखिया) का शव सूखी सेवनिया थाना क्षेत्र के चोपड़ा कलां में रेलवे ट्रैक पर मिला। घर में जिन चारों सदस्यों के शव मिले, उनके गले कटे हुए थे। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि व्यक्ति ने पहले सभी की हत्या की, इसके बाद ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दोनों घटनास्थलों पर जांच शुरू कर दी है। छाला थाना पुलिस के अनुसार, नरेंद्र साहू (35) नामक युवक ग्राम मालीखेड़ी में पीएमएवाई एलआईजी कॉलोनी में किराए के मकान एलआईजी बी-4 में अपने परिवार के साथ रहता था। सोमवार सुबह घर में नरेंद्र की मां सरस्वती साहू (50), पत्नी सोमलता साहू (29), बेटी कृति साहू (10) और बेटे खुश साहू (6) के शव मिले। सभी के सिर और गले पर चोट के निशान मिले हैं। आशंका है कि किसी धारदार हथियार से उन पर हमला किया गया है। वहीं, परिवार के मुखिया नरेंद्र साहू का शव सूखी सेवनिया थाना क्षेत्र के चोपड़ा कलां में रेलवे ट्रैक पर मिला। पुलिस के अनुसार, परिवार के एक रिश्तेदार को सोमवार सुबह नरेंद्र की मौत की सूचना मिली। वह परिजन को जानकारी देने के लिए मालीखेड़ी स्थित घर पहुंचा, लेकिन काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। फोन पर भी किसी से संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद रिश्तेदार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर घर में प्रवेश किया तो अंदर चार लोगों के शव मिले। भोपाल जोन-4 के डीसीपी आदर्श कांत शुक्ला ने बताया कि शुरुआती जांच में परिवार के मुखिया पर कर्ज का दबाव और मानसिक तनाव होने की बात सामने आई है। परिवार का एक छोटा रेस्टोरेंट था, जो कुछ समय पहले बंद हो गया था। बताया गया है कि नरेंद्र पिछले 15 से 20 दिनों से कोई काम भी नहीं कर रहा था। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि आर्थिक परेशानी का घटना से कोई संबंध था या नहीं। उन्होंने बताया कि दो शव बेड पर मिले हैं।

विपक्ष को मैं ईवीएम मशीन पर बहस की खुली चुनौती देता हूं : अमित शाह

अमित शाह ने हैदराबाद रैली में तेलंगाना में कांग्रेस की जीत पर उठाए सवाल



हैदराबाद,(एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को विपक्षी दलों को मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर खुली बहस की चुनौती दी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उन आरोपों पर सवाल उठाए,जिनमें कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर से फायदा मिलता है। हैदराबाद में एक पार्टी रैली में भाग लेने के बाद मोजमजाही मार्केट में एक भाजपा जनसभा को संबोधित करते हुए, शाह ने सवाल किया कि अगर भाजपा के पक्ष में ईवीएम में हेरफेर की गई थी, तो कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव कैसे जीता? उन्होंने विपक्ष के दावों को चुनौती देने के लिए केरल और तमिलनाडु में गैर-भाजपा सरकारों के गठन का भी हवाला दिया। श्री शाह की यह टिप्पणी कांग्रेस के देशव्यापी वोट बचाओ,देश बचाओ अभियान के बीच आई है,जिसने मतदाता सूची के कथित हेरफेर और नामावली संशोधन के दौरान नाम हटाए जाने को लेकर चिंता जताई है। केंद्रीय गृहमंत्री ने हैदराबाद में भाजपा की एक महा पदयात्रा में भाग लिया, जो निज़ाम कॉलेज से शुरू हुई और मोजमजाही मार्केट पर समाप्त हुई। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और बंदी संजय कुमार, तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन रामचंद्र राव तथा पार्टी के कई सांसद,विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए। केंद्रीय शाह ने मार्ग में पार्टी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और उनसे तेलंगाना में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए काम करने का आह्वान किया। जनसभा में,उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाते हुए उसे हराने का आह्वान किया। 1948 में भारतीय संघ में हैदराबाद के विलय का जिक्र करते हुए,उन्होंने इस प्रक्रिया में सरदार वल्लभभाई पटेल की भूमिका को याद किया और कहा कि पटेल के हस्तक्षेप के कारण ही यह शहर निजाम के शासन से मुक्त हुआ था। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शाह ने आरोप लगाया कि तेलंगाना कांग्रेस नेतृत्व के लिए एक एटीएम बन गया है। उन्होंने कथित आरआर टैक्स का जिक्र किया और दावा किया कि राहुल गांधी को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य में पैसा एकत्र किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम या बीआरएस कांग्रेस के भ्रष्टाचार को रोक सकती हैं,और जोर देकर कहा कि केवल भाजपा ही ऐसा कर सकती है।

राष्ट्र भक्ति की अलख जगाता दैनिक
राष्ट्रीय गरिमा
राष्ट्र एक बगीचा है और हम सब इसके माली
भोपाल, मंगलवार 03 नवम्बर 2026
www.rashtriyagarima.com

नेहरू वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, अब वोट चोरी का झूठा नैरेटिव गढ़ रही कांग्रेस : विश्वास सारंग



इंदिरा गांधी के कार्यकाल और कांग्रेस के इतिहास पर उठाए सवाल, बोले—देश के संसाधनों पर नागरिकों का अधिकार

हरदा। मध्यप्रदेश शासन के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग हरदा में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस द्वारा वोट चोरी के आरोप लगाए जाने, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्क्रुक्र) का विरोध करने को लेकर तीखा हमला बोला। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि कांग्रेस को वोट चोरी के आरोप लगाने से पहले अपने इतिहास में झांकना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने से जुड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर लोकतांत्रिक परंपराओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। यह पदयात्रा हरदा की आम जनता द्वारा आयोजित गैर-राजनीतिक आयोजन थी, जिसमें किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं लगाया गया। इसमें विभिन्न समाजों के अध्यक्षों, वित्त विशेषज्ञों, खिलाड़ियों, डॉक्टरों, वकीलों, महिलाओं के प्रतिनिधियों और युवाओं ने भागीदारी की। नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर का हवाला देकर कांग्रेस को घेरा मंत्री श्री सारंग ने कहा कि आज कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगाकर लोकतंत्र को खतरे में बताने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसे अपने अतीत को भी देखना चाहिए। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने से जुड़े कांग्रेस के ऐतिहासिक घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि नेहरू प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत गए थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए भी कांग्रेस के लोकतांत्रिक आचरण पर सवाल उठाए। श्री सारंग ने कहा कि जो कांग्रेस अपने इतिहास में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर सवालों के घेरे में रही है, वह आज चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। लोकतंत्र में जनता का मत सर्वोपरि है और जनादेश का सम्मान करना प्रत्येक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। 12 बार स्क्रुक्रहुआ, तब कांग्रेस ने क्यों नहीं उठाए सवाल? मंत्री श्री सारंग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्क्रुक्र) को लेकर कांग्रेस के विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में पहले भी कई बार स्क्रुक्रकी प्रक्रिया हो चुकी है। उनके अनुसार, 12 बार स्क्रुक्रहोने के दौरान 10 बार कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उस समय कांग्रेस ने इस प्रक्रिया पर ऐसे सवाल नहीं उठाए। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि आज जब मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए स्क्रुक्र की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तब कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। आखिर पहले यही प्रक्रिया होने पर कांग्रेस ने सवाल क्यों नहीं उठाए? उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का विरोध सिद्धांतों पर आधारित नहीं, बल्कि राजनीतिक हितों से प्रेरित है। देश के संसाधनों पर नागरिकों का अधिकार, घुसपैठियों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा श्री सारंग ने कहा कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार देश के नागरिकों का है। मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है।

बरखेड़ा अम्बेका की डेयरी पर छापा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सहित मिलावट की सामग्री जब्त



मंदसौर। जिले के गरोठ क्षेत्र में मिलावटी दूध के कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बरखेड़ा अम्बेका गांव स्थित एक डेयरी पर छापा मारा। यहां से हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दूध पाउडर, राइस ऑयल, करीब एक किलो घी और किसानों से एकत्रित किया गया दूध सहित अन्य संदिग्ध सामग्री जब्त की गई। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बरामदगी से मामले की गंभीरता बढ़ गई है। मुखबिर से मिली सूचना पर गरोठ एसडीएम राहुल चौहान और नायब तहसीलदार जिनेंद्र निगम ने डेयरी का निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान गरोठ थाना प्रभारी बलवीर यादव भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने डेयरी संचालक विनोद पिता रमेश गुर्जर निवासी बरखेड़ा अम्बेका को हिरासत में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जब्त सामग्री के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजने की प्रक्रिया शुरू की है। पुलिस ने विनोद गुर्जर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 274, 275 एवं 110 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच रिपोर्ट से ही सामग्री में मिलावट और उसके स्वरूप का खुलासा होगा। जिले में मिलावटी दूध के खिलाफ इस वर्ष यह पांचवीं कार्रवाई बताई जा रही है। इससे पहले डूंगरखेड़ी, चचावदा पठारी, आमरा और कोटड़ा बुजुर्ग में भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। बरखेड़ा अम्बेका की डेयरी से दूध की आपूर्ति किन-किन क्षेत्रों में की जा रही थी, इसकी भी जांच की जा रही है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मौजूदगी ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और आम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अब जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि जब्त सामग्री का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा था और इस कारोबार से जुड़े अन्य लोग कौन हैं।

शराब माफिया के आगे बेबस मोहन सरकार! जहरीली शराब से मौतों से लेकर पुलिस अधिकारी की हत्या तक : जीतू पटवारी

राष्ट्रीय गरिमा समाचार भोपाल। मध्य प्रदेश में शराब माफिया के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार, जहरीली शराब से हो रही मौतें और अब अवैध शराब की तस्करी रोकने पहुंचे पुलिस अधिकारी की ट्रक से कुचलकर हत्या—ये घटनाएं प्रदेश की कानून-व्यवस्था और मोहन सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। खातेगांव में थाना प्रभारी दिलीप पुरी अपनी टीम के साथ नेमावर रोड हाईवे पर अवैध शराब की तस्करी रोकने पहुंचे थे। इसी दौरान शराब तस्करी में इस्तेमाल हो रहे ट्रक के चालक ने कथित तौर पर उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना बताती है कि प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार करने वाले अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। सितंबर 2026 में सागर जिले के नौराजा, घूघरा खुर्द और आसपास के गांवों में जहरीली शराब के सेवन से कई लोगों की मौत का मामला सामने आया। सवाल यह है कि आखिर प्रशासन की नाक के नीचे जहरीली शराब का कारोबार कैसे फलता-फूलता रहा? देवास जिले के चंदाना-बिंजाना और आसपास के क्षेत्रों में अक्टूबर 2026 में संदिग्ध जहरीली शराब से मौतों का मामला सामने आया। पुलिस जांच में कथित तौर पर नकली शराब तैयार करने, रसायनों की खरीद और लाइसेंसी दुकानों से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका की पड़ताल की गई।, तो आबकारी विभाग की निगरानी और जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की मांग है कि खातेगांव, सागर और देवास की घटनाओं की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। अवैध शराब के पूरे नेटवर्क और उसे संरक्षण देने वालों को बेनकाब किया जाए। दिवंगत थाना प्रभारी दिलीप पुरी के परिवार को उचित सहायता और सम्मान दिया जाए ।

'मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान' के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में संपर्क अभियान 2026 को मिली बड़ी सफलता

राष्ट्रीय गरिमा समाचार भोपाल/ग्वालियर। बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का उनके घर के नजदीक त्वरित समाधान उपलब्ध कराने तथा मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संचालित संपर्क अभियान 2026 को उल्लेखनीय सफलता मिली है। 14 मई से प्रारंभ हुए इस विशेष अभियान के अंतर्गत भोपाल एवं ग्वालियर रीजन के 16 जिलों में अब तक 7103 विशेष शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 3 लाख 9 हजार 263 उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया गया। अभियान के माध्यम से उपभोक्ताओं को स्थानीय स्तर पर सुविधाजनक एवं त्वरित समाधान उपलब्ध कराते हुए विद्युत सेवाओं में पारदर्शिता, सुगमता और उपभोक्ता संतुष्टि को बढ़ावा दिया जा रहा है। भोपाल रीजन के अंतर्गत शहर वृत्त भोपाल में 522 शिविरों में 33,252 शिकायतों का निराकरण किया गया। बैतूल वृत्त में 628 शिविरों में 40,608 शिकायतों का निराकरण, भोपाल (ओ एंड एम) वृत्त में 366 शिविरों में 13,852 शिकायतों का निराकरण, हरदा वृत्त में 190 शिविरों में 22,578 शिकायतों का निराकरण, नर्मदापुरम वृत्त में 482 शिविरों में 33,956 शिकायतों का निराकरण, रायसेन वृत्त में 357 शिविरों में 20,421 शिकायतों का निराकरण, राजगढ़ वृत्त में 515 शिविरों में 8,183 शिकायतों का निराकरण, सीहोर वृत्त में 456 शिविरों में 11,014 शिकायतों का निराकरण तथा विदिशा वृत्त में 306 शिविरों में 16,557 शिकायतों का निराकरण किया गया। ग्वालियर रीजन के अंतर्गत शहर वृत्त ग्वालियर में 419 शिविरों में 10,811 शिकायतों का निराकरण किया गया।

युवाओं के नवाचार से आसान बनेगा समाज का जीवन : इंदरसिंह परमार

धर्मराजेश्वर में भारतीय राष्ट्रीय युवा संसद अधिवेशन का समापन, मंत्री ने युवाओं से किया संवाद



मंदसौर। जिले के ऐतिहासिक धर्मराजेश्वर मंदिर परिसर, चंदवासा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय युवा संसद अधिवेशन का समापन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदरसिंह परमार ने युवाओं से समाज के हित में नवाचार करने और लोगों के जीवन को सरल एवं खुशहाल बनाने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। परमार ने कहा कि युवा भविष्य के बारे में सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है, वैसा ही बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। युवाओं को सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए समाज के लिए उपयोगी बनना चाहिए। वे केवल समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय उनके समाधान खोजने वाले बनें। उन्होंने जल एवं बिजली संरक्षण के साथ पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करने की अपील भी की। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार का उल्लेख करते हुए कहा कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और गरीबों के जीवन में बदलाव लाना सरकार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में योग आयोग अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार, सुवासरा विधायक हरदीपसिंह डंग, गरोठ विधायक चंदर सिंह सिसोदिया, पूर्व विधायक देवीलाल धाकड़ सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी विचार व्यक्त किए। युवा संसद के दौरान प्रतिभागियों ने योगाभ्यास किया तथा मंत्री परमार ने युवाओं के सवालों के जवाब देते हुए उनसे संवाद किया। रितेश गुप्ता, माधुरी चौहान, प्रवीण आक्या जैन, प्रदीप सैनी, अजय शशांक एवं ऋषिकेश ने विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे। मंत्री ने भगवान धर्मराजेश्वर के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और भीम गुफा का अवलोकन किया। उन्होंने आयुष विभाग की प्रदर्शनी भी देखी तथा परिसर में पौधारोपण किया। कार्यक्रम में धर्मपुरी गोस्वामी द्वारा लोकगीत एवं लोकसंगीत की प्रस्तुति दी गई। समापन राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ।

दो जिलों में एनडीपीएस के मामलों में फरार 16 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार



दो साल से पुलिस को दे रहा था चकमा, आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 12 अपराध

मंदसौर। राज्य स्तरीय एंटी नारकोटिक्स विशेष अभियान के तहत पिपलियामंडी पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे 16 हजार रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी दो साल से पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था। उसके खिलाफ मंदसौर जिले के पिपलियामंडी थाने सहित उज्जैन जिले के नागदा थाने में एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी जवान सिंह उर्फ निर्मल (40) पिता प्रतापसिंह बावरी निवासी ग्राम अंबाव, थाना पिपलियामंडी है। मध्यप्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रदेशभर में चलाए जा रहे एंटी नारकोटिक्स विशेष अभियान के तहत फरार आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेर सिंह बघेल के पर्यवेक्षण तथा एसडीओपी मल्हारगढ़ पिंटू कुमार बघेल के मार्गदर्शन में पिपलियामंडी थाना प्रभारी विक्रम सिंह इवने के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पिपलियामंडी थाने के अपराध क्रमांक 282/2026 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 एवं 29 तथा अपराध क्रमांक 324/2025 में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्रकरण में फरार था। इन दोनों मामलों में उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक द्वारा अलग-अलग 3-3 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसके अलावा नागदा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज अपराध क्रमांक 279/2025 में फरार होने पर उस पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित था। इस तरह आरोपी पर कुल 16 हजार रुपये का इनाम था। पुलिस के मुताबिक आरोपी आदतन अपराधी है और उसके विरुद्ध चोरी, आबकारी, मारपीट सहित एनडीपीएस एक्ट के कुल 12 अपराध दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पुलिस रिमांड स्वीकृत हुआ है। पुलिस अब उससे अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के स्रोत और नेटवर्क के संबंध में पूछताछ कर रही है। कार्रवाई में थाना प्रभारी विक्रम सिंह इवने, सहायक उपनिरीक्षक संतोष मुनिया, प्रधान आरक्षक वसीम खान, नरेंद्र धनगर, नरेंद्र सिंह चौहान, विजय परमार तथा आरक्षक उदल सिंह, रिंकू सिंह, पवन सिंह बोराना, राहुल पाटीदार, अनिल गुर्जर, नागेश्वर पाटीदार और जुगल किशोर की सराहनीय भूमिका रही।

टिमरनी की तीन कंपोजिट मदिरा दुकानों के लायसेंस निलंबित

हरदा। खातेगांव में पुलिस थाना प्रभारी की वाहन से कुचलकर हुई मृत्यु की गंभीर घटना के बाद आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर श्री दीपक सक्सेना ने टिमरनी वृत्त में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री अमर सिंह बघेल तथा आबकारी आरक्षक श्री अरुण कुमरे एवं श्री कृष्णपाल सिंह डोडियार को कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं कलेक्टर श्री कुमार सत्यम ने लायसेंसी श्री पाटेन्द्र जायसवाल को आवंटित कंपोजिट मदिरा दुकान सोडलपुर रोड टिमरनी, रहटगांव तथा हरदा रोड टिमरनी के लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। साथ ही लायसेंसी को सूचना पत्र जारी कर 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

प्रभारी मंत्री श्री सारंग ने हरदा के दो गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों को किया सम्मानित

हरदा। प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग व सहकारिता मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने सोमवार को हरदा आगमन के अवसर पर जिले के दो प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। जिला खेल अधिकारी श्री विकास खरे कर द्वारा अवगत कराया गया कि ब्लॉक खिरकिया के खिलाड़ी आराध्य वरुण शर्मा ने 10 मीटर एयर रायफल शूटिंग में राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल जीता है, वहीं हरदा के यस जाट ने हैंडबॉल में राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक अर्जित किया है। इस उपलब्धि पर खेल मंत्री श्री सारंग ने दोनों खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर जिला ओलम्पिक संघ अध्यक्ष श्री संदीप पटेल, खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्री विक्रांत अग्रवाल, ब्लॉक समन्वयक सुश्री सलमा खान, खेल प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक श्री भूपेंद्र सिंह तोमर, सुश्री हीना अली, श्री संदीप जाट, श्री राजेश जालाबड़ा, श्री संदीप सौदे, कोच श्री प्रतीक शर्मा, श्री गौतम विश्वकर्मा सहित अन्य खेल प्रेमी उपस्थित रहे।

25 साल की सैन्य सेवा को सलाम, सूबेदार मेजर बद्रीनारायण जोशी का 805वें सैनिक सम्मान में अभिनंदन

मंदसौर।भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में 25 वर्षों तक सेवाएं देने वाले मंदसौर निवासी सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर बद्रीनारायण जोशी का जिला सैनिक सम्मान अभियान के तहत 805वें सैनिक सम्मान के रूप में भव्य अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न चौराहों पर पुष्पमालाओं, साफा और देशभक्ति के जयघोष के साथ उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता चौराहा पर भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजन के साथ हुई। इसके बाद स्वागत यात्रा गांधी चौराहा पहुंची, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा तथा सरदार पटेल चौराहा पर सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। महाराणा प्रताप चौराहा पर भी देशभक्ति के जयघोष के साथ सैनिक का स्वागत किया गया। इसके बाद स्नेह नगर स्थित जोशी के निवास पर सम्मान समारोह आयोजित हुआ। यहां विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, पूर्व सैनिकों और नागरिकों ने शाल, श्रीफल एवं साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया। भाजपा नेता अनिल कियावत ने कहा कि सेना के जवानों का त्याग, अनुशासन और समर्पण सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। वरिष्ठ पूर्व सैनिक श्रवण कुमार त्रिपाठी ने सैनिक जीवन को त्याग और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक बताया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जिलाध्यक्ष मुकेश गुर्जर ने कहा कि पूर्व सैनिकों के योगदान को समाज के सामने लाना और उनका सम्मान करना जरूरी है।

छोटा विज्ञापन
बड़ा लाभ
छोटा विज्ञापन
बड़ा लाभ



क्लासीफाईड विज्ञापन दरें
150/- रूपये प्रतिदिन 25 शब्दों तक
स्कीम
2 दिन के विज्ञापन पर 2 दिन अतिरिक्त प्रकाशन
5 दिन के विज्ञापन पर 10 दिन अतिरिक्त प्रकाशन
10 दिन के प्रकाशन पर 20 दिन अतिरिक्त प्रकाशन
राष्ट्रीय गरिमा समाचार पत्र में विज्ञापन देकर अपने व्यापार को दें नई उड़ान
सम्पर्क करें : 8602000710, 8602000703
मात्र 1500/- रूपये में पूरे एक माह चलायें

बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए लगा विधिक शिविर



मंदसौर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार संचालित 'सुरक्षित बचपन अभियान' के तहत करणी इंटरनेशनल स्कूल में 'मेरा बचपन, मेरा अधिकार' थीम पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनीष कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा और कानूनी संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिद्धार्थ तिवारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी अपर्णा लोधी तथा विद्यालय के प्राचार्य महावीर सक्सेना उपस्थित रहे। शिविर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिश्रा ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करना केवल परिवार ही नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है। हर बच्चे को भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए, जिससे वह अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए व्यक्तित्व का समुचित विकास कर सके। इस अवसर पर उन्होंने सुरक्षित बचपन अभियान के ब्रोशर का विमोचन भी किया। विद्यार्थियों को बाल विवाह, बाल श्रम, शारीरिक एवं मानसिक शोषण तथा हिंसा से बचाव के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही असुरक्षित परिस्थितियों को पहचानने, सतर्क रहने और किसी भी अनुचित व्यवहार या अप्रिय घटना की स्थिति में बिना भय के अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित प्राधिकरण को सूचना देने के लिए प्रेरित किया गया। जिला न्यायाधीश एवं सचिव सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी होना उनकी सुरक्षा और सशक्तीकरण का आधार है।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी उपेन्द्र तिवारी द्वारा प्रदेशवॉच मीडिया ग्रुप 11 प्रेस कम्प्लेक्स जोन 1 एमपी नगर भोपाल से मुद्रित एवं बी-14 कस्तूरबा नगर भोपाल से प्रकाशित। सम्पादक : अभिमन्यु तिवारी,सहायक सम्पादक : शैलेन्द्र तिवारी।
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा। (समाचार प्रकाशन के लिये पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार*) आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक 61858/95, मो. 8602000710 , 8602000701

दैनिक
राष्ट्रीय गरिमा
शुभ प्रभात
www.rashtriyagarima.com
भोपाल, मंगलवार 03 नवम्बर 2026

दीपावली से पहले पटाखा फैक्ट्रियों में अग्नि सुरक्षा को लेकर की जांच

हरिद्वार। दीपावली पर्व और आगामी त्योहारों के मद्देनजर अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस और अग्निशमन विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह के निर्देश पर अग्निशमन विभाग की टीम ने रुड़की क्षेत्र स्थित विभिन्न पटाखा फैक्ट्रियों एवं इकाइयों का स्थलीय निरीक्षण कर अग्नि सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया।

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम में मत्स्य पालन का लिया जायजा

गंगटोक। केंद्रीय पंचायती राज,मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सोमवार को उत्तर सिक्किम के मंगन जिले का दौरा कर मत्स्य पालन और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मांगशिला स्थित थेगिम मार्ट में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत संचालित जीवित मछली बिक्री केंद्र का निरीक्षण किया।

केंद्र सरकार से बढ़ती दूरी के लिए एनसी नेतृत्व है जिम्मेदार : महबूबा मुफ्ती

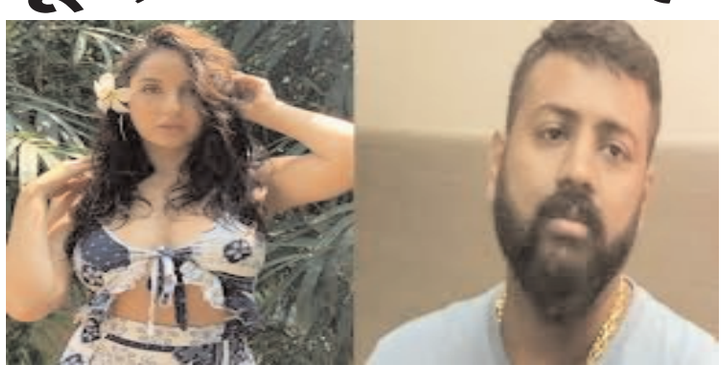
महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित



श्रीनगर,(एजेंसी)। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना की। उन्होंने जम्मू-कश्मीर और केंद्र के बीच बढ़ती दूरी के लिए एनसी के नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर पार्क में पीडीपी के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यकर्ताओं के एक बड़े सम्मेलन को संबोधित करते हुए महबूबा ने सवाल किया कि कश्मीरियों को लगातार शक की नजर से क्यों देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को परेशान कियाजा रहा है, कश्मीरी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है और आदिवासी समुदायों को उनकी जगहों से बेदखल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को हमारे ऊपर इतना शक क्यों है हमारे युवाओं को पीटा जा रहा है, कश्मीरी अधिकारियों को नौकरी से हटाया जा रहा है और आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। इस पर सोचने की जरूरत है। एनसी पर निशाना साधते हुए महबूबा ने कहा कि प्रधानमंत्री (वजीरे-आजम) के पद से हटकर मुख्यमंत्री (वजीरे-आला) की व्यवस्था अपनाने के बाद इस पार्टी ने स्वायत्तता (ऑटोनॉमी) की मांग को ही दफना दिया। उन्होंने कश्मीर में उग्रवाद (मिलिटेंसी) के मुश्किल दौर के लिए भी एनसी के नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में लोगों ने बहुत कष्ट झेले और आरोप लगाया कि उस दौरान पार्टी ने %इख्वान% बलों का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान पर एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बयानों का जिक्र करते हुए महबूबा ने कहा कि कश्मीरियों ने पहले ही अपना फैसला ले लिया है और वे भारत के साथ खड़े हैं। जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की भूमिका को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बावजूद उन्होंने देश पर भरोसा जताया था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के साथ उनके संबंधों का भी जिक्र किया। महबूबा ने बताया कि शेख अब्दुल्ला ने शांति बहाल करने में मदद के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जम्मू-कश्मीर बुलाया था। उन्होंने मुगल रोड के निर्माण का भी उल्लेख किया। महबूबा ने कहा कि पीडीपी की स्थापना जम्मू-कश्मीर की गरिमा और पहचान को बहाल करने के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी ने कभी कोई दोहरा एजेंडा नहीं अपनाया। उन्होंने भारत सरकार से जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत शुरू करने का आग्रह किया और सवाल किया कि आखिर कब तक इस क्षेत्र पर ताकत के दम पर शासन किया जा सकता है। 10 अक्टूबर को दिल्ली में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों के गुस्से और चिंताओं को समझना चाहिए न कि जबरदस्ती के तरीकों से शांति दिखाने की कोशिश करनी चाहिए।

कोर्ट में पेश नहीं हुईं नोरा फतेही,वकील ने मांगी छूट,जज ने जताई नाराजगी

सुकेश चंद्रशेखर केस से जुड़े 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली का मामला



नई दिल्ली (एजेंसी)। बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही एक बार फिर सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में अदालत में पेश नहीं हुईं। सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी। नोरा को अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर अपना बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेश होना था, लेकिन वह नहीं पहुंचीं। नोरा फतेही की ओर से वकील ने अदालत में पेश होने से छूट देने की मांग की। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अदालत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तारीख तय की है। अब नोरा को उस दिन गवाही के लिए अदालत में पेश होना होगा। सोमवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि नोरा फतेही आज कोर्ट में पेश होंगी या नहीं। पुलिस ने बताया कि अभिनेत्री को 22 अक्टूबर को ही पेशी का नोटिस भेज दिया गया था। यह नोटिस ईमेल और व्हाट्सऐप के जरिए भेजा गया था। इसके अलावा, उन्हें फोन भी किया गया, लेकिन नोरा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वहीं, नोरा के वकील ने अदालत में पेश होने से छूट देने की मांग की। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि अदालत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोरा को 2 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। उन्हें इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह के तौर पर अपना बयान दर्ज कराना था। अब अदालत ने अगली सुनवाई 6 नवंबर को रखी है। दरअसल, नोरा फतेही का नाम सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े इस मामले में तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर शामिल है। जांच एजेंसियों के मुताबिक,सुकेश ने जेल में रहते हुए करीब 200 करोड़ रुपये की ठगी की थी। इस मामले में शिकायत फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह ने दर्ज कराई थी। आरोप था कि सुकेश ने खुद को सरकारी अधिकारी बताकर उनसे संपर्क किया और उनके पति को जेल से बाहर निकलवाने में मदद करने का भरोसा दिया। इसी बहाने उसने उनसे करोड़ों रुपये वसूले। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने की थी। जांच के दौरान सुकेश का नाम बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों से भी जुड़ा। इनमें नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडीज का नाम सामने आया। जांच एजेंसियों के मुताबिक, सुकेश ने अभिनेत्रियों से संपर्क बनाने के लिए पिंकी ईरानी की मदद ली थी। आरोप था कि पिंकी ने सुकेश की पहचान और उसके रसूख को अलग तरीके से पेश करके अभिनेत्रियों को उससे मिलवाया था। सितंबर 2022 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नोरा से कई घंटों तक पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान नोरा ने बताया था कि वह सुकेश की पत्नी लीना मारिया पॉल की ओर से आयोजित एक चैरिटी शो में शामिल हुई थीं।

अमिताभ बच्चन ने मीडिया पर लगाया शब्दों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप

मीडिया पर भड़के मेगास्टार अमिताभ बच्चन,बयान में कहा सोच लो,भारी पड़ेगा



मुंबई। मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने अपने ताजा एक्स पोस्ट में मीडिया में छपी खबर को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। अमिताभ ने आरोप लगाया है कि उनके शब्दों को मीडिया प्रचार के लिए दूसरे संदर्भ में पेश कर रहा है। इतना ही नहीं, 'सदी के महानायक' ने इसके लिए मीडिया को चेतावनी भी दी है। दरअसल, मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया था। उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए अक्सर इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक पंक्ति, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की से जुड़ा एक पोस्ट और ब्लॉग लिखा था। अमिताभ का कहना है कि मीडिया ने इन शब्दों को तोड़मरोड़कर पेश किया है। अमिताभ ने अपने पोस्ट में मीडिया में संबंधित खबर की हैडिंग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वह कृष्ण कन्हैया के लिए, प्रार्थना स्वरूप, अक्सर हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की का उच्चारण करते हैं और मीडिया ने इसे ही गलत तरीके से पेश किया है। अमिताभ ने स्पष्ट किया कि उनका पोस्ट वास्तव में भगवान कृष्ण के लिए एक प्रार्थना थी और उनके शब्द न किसी राजनीतिक बयान का हिस्सा था, न ही किसी विरोधी पर उन्होंने कोई तंज कसा था। उन्होंने कहा कि मीडिया ने ऐसी खबर छापकर धार्मिक नजरिए से भी गलत किया है। उन्होंने इसे धर्म का निरादर भी बताया। अमिताभ ने कहा, और मीडिया उसका निरादर करके, अपना प्रचार करने के लिए, छापता है, 'देखिए ये अमिताभ अपने विरोधियों को चुनौती दे रहा है, की, 'ले आओ हाथी घोड़ा 'हम अपने हथियारों से लड़ेंगे, डरेंगे नहीं!' एक तो घोर निंदा एक 'जय श्री कृष्ण ' के उपलक्ष्य में, और दूसरा , शब्दों को पलट कर विरोधियों को चुनौती देने की बात कर रहे है। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए, दिग्गज अभिनेता ने मीडिया को एक कड़ा संदेश भी दिया,जिसमें कहा गया कि उनके 5 करोड़ फॉलोअर्स हैं और अगर इशारा मिल जाए तो उनमें से 10 प्रतिशत भी उनके समर्थन में आ जाएंगे। मेगास्टार ने अपने पोस्ट के जरिए यह भी कहा कि जब किसी पब्लिक फिगर से गलती होती है, तो वे माफी मांग लेते हैं, लेकिन जब किसी भी मीडिया की तरफ से गलती होती है, तो उनकी तरफ से कोई माफी नहीं आती है।

मणिपुर में फिर भड़की हिंसा,नोनी जिले में हुई गोलीबारी में तीन की मौत

कुकी इनपी ने की हत्याओं की निंदा, नागा उग्रवादी गुटों पर लगाया आरोप



इंफाल। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में एक बार फिर हिंसक घटनाओं से तनाव गहरा गया है। राज्य के नोनी जिले में एक सुदूर पहाड़ी गांव के जंगलों में दो सशस्त्र गुटों के बीच हुई भीषण गोलीबारी में कुकी समुदाय के तीन लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। दूसरी तरफ, कांगपोकपी जिले से कई दिनों से लापता चल रहे दो युवकों के शव सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान बरामद किए गए हैं। इन दोनों घटनाओं के बाद संबंधित इलाकों में भारी तनाव फैल गया है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, गोलीबारी की यह खूनी वारदात शनिवार सुबह नोनी जिले के अंतर्गत आते केकडू नागा गांव के नजदीकी पहाड़ी इलाके में शुरू हुई। दोनों पक्षों के बीच दुर्गम जंगलों में कई घंटों तक रुक-रुक कर भारी गोलीबारी चलती रही। मुठभेड़ समाप्त होने के बाद मौके से तीन लोगों के गोलियों से छलनी शव बरामद किए गए। मृतकों की पहचान थांगलेंसंग सिंगसन, थांगखोसेई हाओकिप और लम्मिनसंग किपजेन के रूप में की गई है। ये सभी चुराचंदपुर जिले के हेंगलेप और थानलन के अंदरूनी क्षेत्रों के निवासी बताए जा रहे हैं। कुकी नागरिक संगठनों ने दावा किया है कि मारे गए तीनों युवक अपने इलाकों की सुरक्षा में तैनात 'ग्राम स्वयंसेवक' (विलेज वॉलंटियर्स) थे। घटना की जानकारी सामने आते ही कुकी समुदाय के सर्वोच्च प्रतिनिधि निकाय 'कुकी इनपी मणिपुर' ने कड़ा रोष जताते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया है। संगठन ने हत्याओं की तीखी निंदा करते हुए आरोप लगाया कि इस कायरतापूर्ण हमले के पीछे नगा उग्रवादी समूहों का हाथ है। संगठन ने केंद्र और राज्य सरकार से मामले में अविलंब उच्च स्तरीय जांच, दोषियों की पहचान कर जवाबदेही तय करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कर गश्त बढ़ा दी गई है।

दिवाली से पहले दिल्ली में घुटने लगा लोगों का दम,हवा बनी जानलेवा

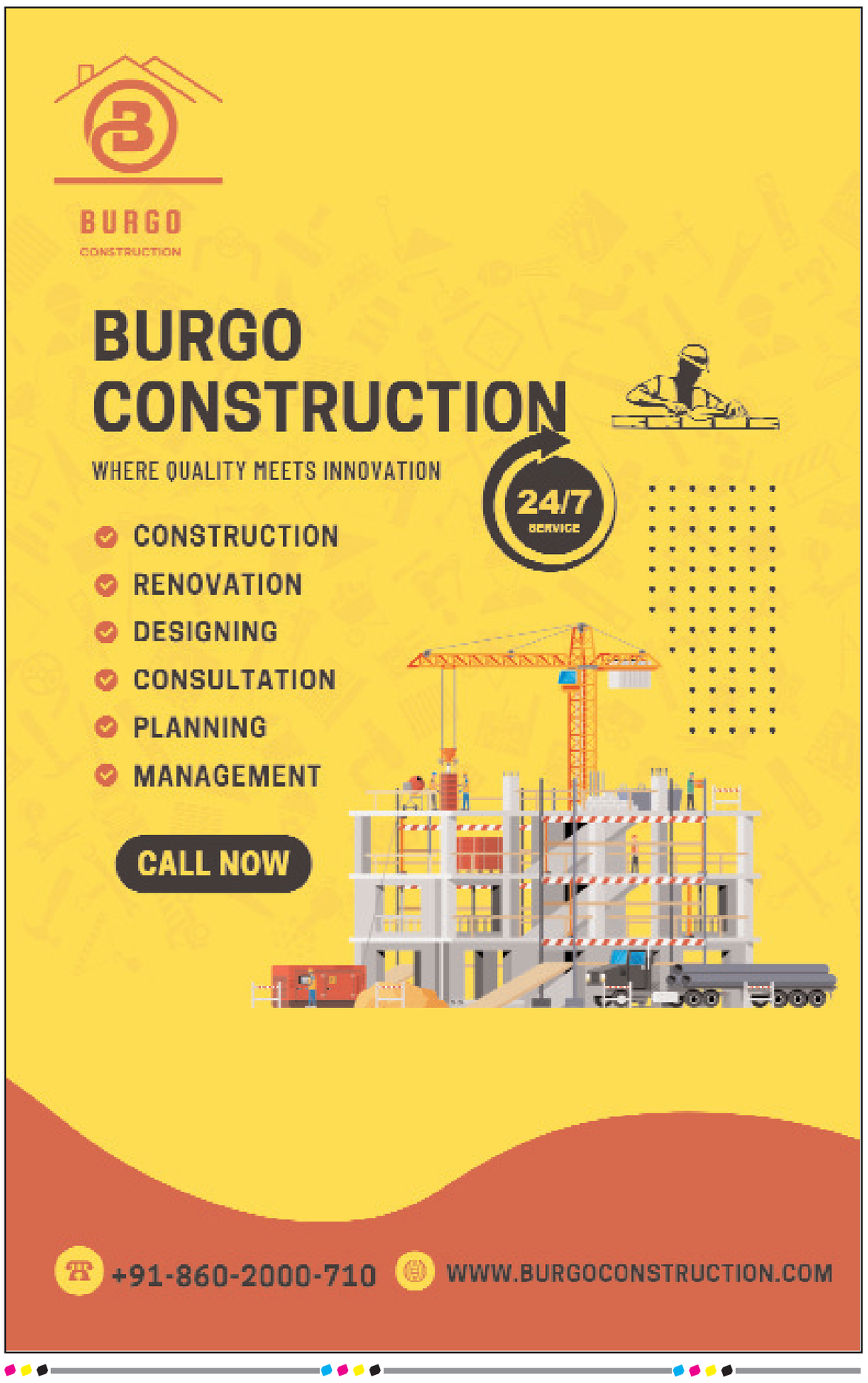


कई इलाकों में एक्यूआई 400 पार,जहांगीरपुरी में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली से पहले वायु प्रदूषण ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। शहर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल होने लगा है। सोमवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 350 के पार पहुंच गया। समीर ऐप के अनुसार,जहांगीरपुरी में सबसे अधिक 420 एक्यूआई दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं, पंजाबी बाग और रोहिणी में भी एक्यूआई 399 तक पहुंच गया। सुबह के आंकड़ों के मुताबिक, सुनीता विहार में एक्यूआई 370, सिरीफोर्ट में 354, तालकटोरा गार्डन में 322, उत्तम नगर में 310, विवेक विहार में 376, वजीरपुर में 322, ओखला फेज-2 में 350, पटपड़गंज में 357, पंजाबी बाग में 399, पूसा में 340, आरके पुरम में 370, रोहिणी में 399, मुद्रिका में 377, नजफगढ़ में 313, नांगलोई में 319 और नरेला में 375 दर्ज किया गया। इसके अलावा मंदिर मार्ग पर 340, नॉर्थ कैंपस (डीयू) में 359, आईआईटी दिल्ली में 337 और जहांगीरपुरी में 420 एक्यूआई रहा। इसी तरह आईटीओ में 351, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 349, जेएनयू में 319, चांदनी चौक में 361, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 332, मथुरा रोड पर 334, द्वारका सेक्टर-8 में 357, अलीपुर में 382, अशोक विहार में 327, बवाना में 365 और बुराड़ी क्रॉसिंग पर 354 एक्यूआई दर्ज किया गया। हालांकि,आईजीआई एयरपोर्ट पर यह आंकड़ा 294, लोधी रोड पर 251 और नेहरू नगर में 289 रहा। गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक नवंबर से नए प्रतिबंध लागू किए गए हैं, लेकिन इन पाबंदियों के पहले ही दिन यानी रविवार को हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। इससे पहले दिल्ली में बारिश के कारण दो दिनों तक प्रदूषण से कुछ राहत मिली थी, लेकिन रविवार को स्थिति फिर बिगड़ गई। यह दिन न केवल मौजूदा सीजन का, बल्कि 12 जुलाई के बाद से सबसे अधिक प्रदूषित दिन दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मानकों के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक को छह श्रेणियों में बांटा गया है। 0 से 50 तक एक्यूआई अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 गंभीर श्रेणी में माना जाता है।

काशी में अन्नपूर्णा महोत्सव में 150 क्विंटल पकवानों से महकी नगरी

वाराणसी। वाराणसी में दीपावली के पावन उत्सवों के चरम काल में मां अन्नपूर्णा मंदिर में भव्य अन्नकूट महोत्सव की तैयारियां पूरे उत्साह से जारी हैं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी (धनतेरस), 6 नवंबर को स्वर्णमयी माता अन्नपूर्णेश्वरी के दर्शन के लिए मंदिर के पट खुल जाएंगे, जिसके साथ ही खजाना वितरण भी आरंभ होगा। चार दिनों तक चलने वाले दर्शन के बाद, 10 नवंबर को होने वाले अन्नकूट महोत्सव को लेकर मंदिर परिसर पकवानों की सुगंध से महक उठा है। मां अन्नपूर्णा की रसोई में 85 दक्ष कारीगरों का एक दल 150 क्विंटल मिष्ठान और नमकीन तैयार करने में जुटा है। देवी को भोग लगाने के लिए बेसन, मैदा, खोवा-चीनी के लड्डू,काजू, बादाम, चिरौंजी, गरी, खोवा सहित सात प्रकार की बर्फी, खुर्मा, बालूशाही, खजूर के गुड़ की जलेबी और गुलाब जामुन जैसे विविध प्रकार के मिष्ठान बनाए जा रहे हैं। इनके साथ ही 35 प्रकार के नमकीन भी तैयार किए जा रहे हैं, जो इस महोत्सव को और भी खास बना रहे हैं। अन्नकूट पर माता को 51 क्विंटल खान-पान का विशाल भोग लगाया जाएगा।



राष्ट्र भक्ति की अलख जगाता दैनिक
राष्ट्रीय गरिमा
राष्ट्र एक बगीचा है और हम सब इसके माली
भोपाल, मंगलवार 03 नवम्बर 2026
www.rashtriyagarima.com

सम्पादकीय

देश को भरोसे में लेना चाहिए

क्या चीन से संबंध सुधारने की प्रक्रिया इस पराजयवादी मानसिकता के तहत चल रही है कि चीन का मुकाबला करना संभव नहीं रह गया है? सरकार को इस पर तुरंत देश को भरोसे में लेना चाहिए। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के निदेशक शत्रुजित कपूर के सनसनीखेज भाषण के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी फौज के गश्ती के तय रास्ते से भटकने के कारण अक्सर भारतीय बलों के साथ उसका टकराव हो जाता है। उसके एक दिन पहले कपूर ने कहा था कि 'पिछले कुछ दिनों में ऐसे हालात बने, जब अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर दोनों देशों के सुरक्षा बलों का आमना-सामना हुआ और यह अभी भी जारी है।' इस बयान ने यह साफ किया कि भारत और चीन के बीच हाल की सीमा वार्ताओं में बनी सहमतियां जमीनी स्तर पर टकराव टालने में कामयाब नहीं हुई हैं। इससे उचित ही चीन के साथ संबंध के बारे में भारत सरकार की नीति पर सवाल खड़े हुए। बहरहाल, उससे भी कहीं ज्यादा अहम कपूर की दूसरी टिप्पणी है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब पारंपरिक तरीकों से चीन का मुकाबला करना संभव नहीं है, क्योंकि उसने हथियार और इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण में भारी निवेश किया है। ऐसे में कपूर ने भारत को ड्रोन्स पर भरोसा करने की सलाह दी। इस बात का जिक्र करते हुए कि यूक्रेन ने ड्रोन्स के जरिए रूस जैसी महाशक्ति को चुनौती दी है, कपूर ने कहा- 'ड्रोन ऐसा माध्यम हैं, जिनके जरिए एक छोटा देश भी बड़े देश को चुनौती दे सकता है।' हैरतअंगेज है कि जिस बल पर चीन से लगी भारतीय सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी है, उसके प्रमुख अब चीन के बरक्स को भारत को छोटी ताकत बता रहे हैं! कपूर ने कहा कि आईटीबीपी 50 साल पुराना बल है, जिसके आधुनिकीकरण की जरूरत है। तो सवाल उठता है कि क्या गलवान घाटी जैसी घटना के बावजूद इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए? और क्या अभी चीन से संबंध सुधारने की जारी प्रक्रिया इसी पराजयवादी मानसिकता के तहत चल रही है कि चीन का मुकाबला करना संभव नहीं रह गया है? नरेंद्र मोदी सरकार को इस पर तुरंत सारे देश को भरोसे में लेना चाहिए। वरना, ऐसी टिप्पणियों का देशवासियों के मनोबल पर स्थायी और दूरगामी नकारात्मक असर पड़ सकता है।

राशिफल



मेष राशिः आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपको घर के बड़ों से कुछ प्रेरणा मिलेगी। आज आप जो भी काम शुरू करेंगे, वह सफल होगा। आज आपका स्वास्थ्य पहले से उत्तम रहेगा। रिश्तेदार आज आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए सुझाव देंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बड़े-बुजुर्ग आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे।

वृष राशिः आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज पूरा दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आपके आस-पास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। लोग आपके व्यवहार से खुश रहेंगे। आप किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से पार्टनरशिप करने पर विचार करेंगे। आज आपको उम्मीद से ज्यादा धन लाभ होने वाला है।

मिथुन राशिः आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला होगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं, लेकिन पढ़ाई में और मेहनत करने की जरूरत है। आज घरवालों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जूनियर आपसे काम सीखना चाहेंगे।

कर्क राशिः आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है। आज पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें। नौकरी कर रहे लोगों को आज अपना काम पूरा करने के लिए थोड़ा अधिक मेहनत करने की जरूरत है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा का बेहतर परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहने वाला है।

सिंह राशिः आज पूरे दिन भाग्य आपके साथ रहेगा। आज किसी अनजान व्यक्ति के सहयोग से आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस राशि के केमिस्ट शॉप वाले लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। आज आप अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाने की योजना बनाएंगे। महिलाएं आज रसोईघर में व्यस्त रहेंगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ बरकरार रहेंगी।

कन्या राशिः आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आपको सरकारी कामों में कुछ लोगों से राय मिलेगी, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। आज आपका पुराना दोस्त आपको फोन करके आपको सरप्राइज देगा। आपकी किसी जरूरी बात पर घर वाले सहमति जताएंगे। तरक्की आज आपके कदम चूमेगी।

तुला राशिः आज का दिन मिली-जुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। आप सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। आज आपकी तरक्की के कई रास्ते खुलेंगे। आज आप अपने बिजी दिन में कुछ समय अपने लिए निकालेंगे, उस समय में अपने पसंदीदा कार्य करेंगे। आज किसी से भी उलझने से आपको बचना चाहिए। बच्चों को आज पढ़ाई में मन लगाने की जरूरत है।

वृश्चिक राशिः आज आपको किसी अपने से अच्छी खबर मिलने के योग बने हुए हैं। आज आप अपने घरेलू कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। आज आपके सकारात्मक रवैये से जीवनसाथी प्रसन्न रहेंगे। जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जाएंगे। मार्केटिंग की जॉब कर रहे लोगों से आज नया क्लाइंट जुड़ेगा, जो भविष्य में अच्छा धन लाभ कराएगा।

धनु राशिः आज का दिन जीवन में मील का पत्थर साबित होगा। आज व्यापार में किसी ऐसी कंपनी के साथ डील फाइनल होगी, जो आपको उम्मीद से अधिक फायदा कराएगी। वकीलों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, नया केस हाथ लगेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी, जीवनसाथी के साथ आज मूवी देखने का मन बनाएंगे।

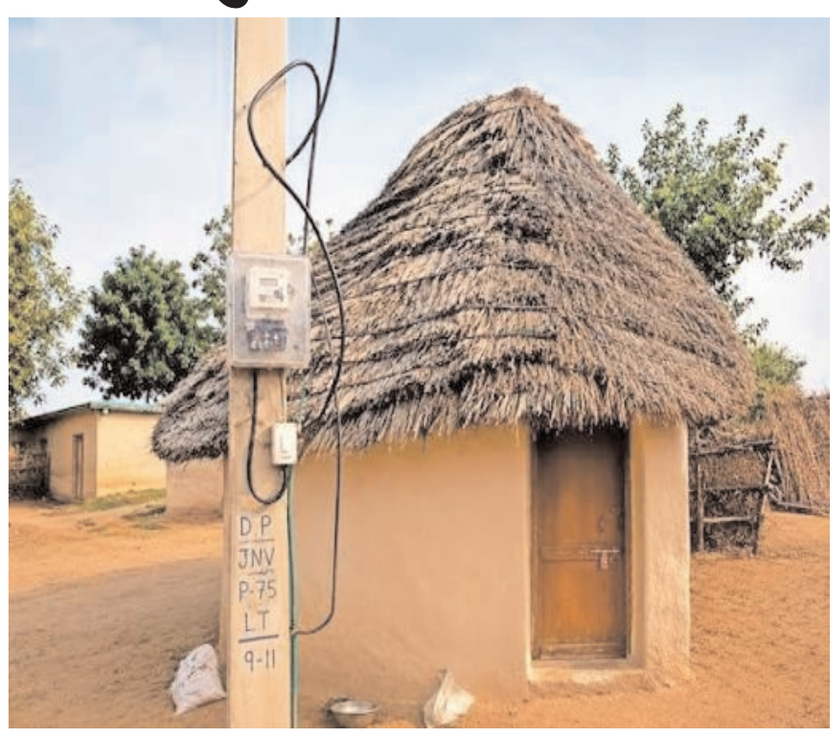
मकर राशिः आज आपका दिन ठीक-ठाक रहने वाला है। आज आपको किसी भी प्रकार के विवादों से दूर रहने की आवश्यकता है। आज बिना सोचे-समझे किसी अजनबी पर भरोसा ना करें। इस राशि के छात्रों को आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किसी विषय को समझने में आपको अपने सहपाठियों से सहयोग मिलेगा।

कुंभ राशिः आज आपकी हर परेशानी का हल चुटकियों में निकल जाएगा। ऑफिस में आप किसी प्रोजेक्ट के लिए अपनी बेहतरीन राय देंगे, बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। आज आप लेखन कार्यों में रुचि लेंगे, आपका लेखन और अच्छा होगा।

मीन राशिः आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। बड़े निर्णय लेने के लिए दिन अच्छा है। किसी नई बिजनेस डील के लिए ऑफर मिलेगा। आप जीवनसाथी के साथ घर के कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए दिन अच्छा है। बेटी के ससुराल पक्ष से बड़ी खुशखबरी मिलेगी। बच्चे आज अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस रहेंगे।

आजादी के बाद पहली बार ग्राम चांगेर में पहुंची विकास की रोशनी

धनंजय राठौर, ताराशंकर सिन्हा,



जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) मद से कराए गए विद्युतीकरण कार्य के फलस्वरूप गांव के सभी 23 घर अब रोशनी से जगमगा उठे हैं। अंधेरे से उजाले तक का सफरनामा प्रशासनिक और भौगोलिक कारणों से जिन क्षेत्रों में आठ दशकों तक बिजली नहीं पहुँच पाई थी, वहाँ सरकारी प्रयासों और विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के जरिए रोशनी पहुँची है। ग्राम चांगेर के ग्रामीण वर्षों से बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित थे। शाम ढलते ही गांव में अंधेरा छा जाता था। बच्चों को पढ़ाई के लिए लालटेन का सहारा लेना पड़ता था, वहीं रात के समय आवागमन में भी ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बिजली के अभाव में दैनिक जीवन के अनेक कार्य प्रभावित होते थे। ऐसे में गांव में विद्युतीकरण होना ग्रामीणों के लिए लंबे इंतजार के बाद पूरी हुई एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िले के अबूझमाड़ क्षेत्र के कई दूरदराज और नक्सल-प्रभावित गांवों में दशकों के अंधेरे के बाद पहली बार बिजली पहुंचाई गई है। छत्तीसगढ़ शासन की मंशानुरूप दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कर ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोण्डागांव जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित अति दुर्गम ग्राम चांगेर में आजादी लगभग 8 दशकों में पहली बार बिजली पहुंची है। जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) मद से कराए गए विद्युतीकरण कार्य के फलस्वरूप गांव के सभी 23 घर अब रोशनी से जगमगा उठे हैं। अंधेरे से उजाले तक का सफरनामा प्रशासनिक और भौगोलिक कारणों से जिन क्षेत्रों में आठ दशकों तक बिजली नहीं पहुँच पाई थी, वहाँ सरकारी प्रयासों और विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के जरिए रोशनी पहुँची है। ग्राम चांगेर के ग्रामीण वर्षों से बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित थे। शाम ढलते ही गांव में अंधेरा छा जाता था। बच्चों को पढ़ाई के लिए लालटेन का सहारा लेना पड़ता था, वहीं रात के समय आवागमन में भी ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बिजली के अभाव में दैनिक जीवन के अनेक कार्य प्रभावित होते थे। ऐसे में गांव में विद्युतीकरण होना ग्रामीणों के लिए लंबे इंतजार के बाद पूरी हुई एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ग्राम चांगेर के सभी 23 घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए ग्राम चांगेर तक विकास की रोशनी पहुंचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) मद से 25.21 लाख रुपये की लागत से विद्युतीकरण कार्य कराया गया। इसके तहत गांव के सभी 23 घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इस पहल से ग्रामीणों को बुनियादी सुविधा मिलने के साथ ही उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव की नई संभावनाएं भी बनी हैं। लंबे समय से अंधेरे में जीवन गुजार रहे कई गाँवों और मजरों में पहली बार बिजली के बल्ब और स्मक् की रोशनी पहुँची है। बिजली आने से ग्रामीणों और बच्चों को अंधेरे से राहत मिली है तथा रात के समय कामकाज और पढ़ाई में आसानी हुई है। आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम ग्राम चांगेर में बिजली पहुंचने से बच्चों को अब शाम के समय बेहतर रोशनी में पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। साथ ही, ग्रामीणों को घरेलू कार्यों में सुविधा और रात के समय आवागमन में सहूलियत मिलेगी। बिजली की उपलब्धता से शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और स्वरोजगार से जुड़ी गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। यह सुविधा ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुरक्षित जीवन और बेहतर भविष्य की दिशा में एक नई शुरुआत ग्राम चांगेर में पहली बार बिजली पहुंचने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। ग्रामवासियों ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों के लिए यह केवल बिजली कनेक्शन मिलने की उपलब्धि नहीं, बल्कि वर्षों से प्रतीक्षित सुविधा, सुरक्षित जीवन और बेहतर भविष्य की दिशा में एक नई शुरुआत है। विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहा दूरस्थ चांगेर माओवाद से प्रभावित रहे क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा की स्थिति में सुधार के साथ विकास कार्यों को गति मिल रही है। जिला प्रशासन द्वारा दूरस्थ एवं दुर्गम गांवों तक सड़क, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्राम चांगेर में विद्युतीकरण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो अंतिम छोर पर बसे परिवारों तक विकास का लाभ पहुंचाने और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के संकल्प को दर्शाती है। भारत की आज़ादी के 78 वर्षों बाद कोण्डागांव ज़िले के पूर्व में नक्सल-प्रभावित ग्राम चांगेर में दशकों के अंधेरे के बाद पहली बार बिजली पहुंचाई गई है। ग्रामीण झूम उठे और उनके चेहरों खुशी की लहर दिख रही है। सरकार ने सुदूर ग्रामीणों तक विकास कार्य पहुंचाने का काम किया है। मोदी सरकार का संकल्प स्पष्ट है कि विकास की रोशनी देश के अंतिम छोर तक पहुँचे, और कोई भी गांव अंधेरे में न रहे, उनकी इसी संकल्प को छत्तीसगढ़ की श्री विष्णु देव की सरकार साकार कर रही है। लेखक संयुक्त संचालक, सहायक संचालक, जनसंपर्क रायपुर हैं

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई)



भारत की जनसंख्या का 16.6त्न हिस्सा अनुसूचित जाति (एससी) का है और इन्हें सामाजिक-आर्थिक उन्नति और समावेशन में ऐतिहासिक रूप से बाधाओं का सामना करना पड़ा है। इन असमानताओं को दूर करना सामाजिक न्याय, समान अवसर और भारत के विकास पथ में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन विकास संबंधी कमियों को पहचानते हुए, भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) शुरू की। समावेशी सशक्तिकरण का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू की गई एक पूर्णत: केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण के ज़रिए अनुसूचित जाति समुदायों का सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण करना है। सरकार ने पीएम-एजीएवाई योजना के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन के लिए पीएम-एजेएवाई मोबाइल ऐप और पीएम-एजेएवाई पोर्टल लॉन्च किया है। पीएम-एजेएवाई तीन पूर्व केंद्र प्रायोजित योजनाओं, अर्थात् प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता उप योजना (एससीए टू एससीएसपी) और बाबू जगजीवन राम छात्रवास योजना (बीजेआरसीवाई) का विलय करके बनाई गई योजना है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित पीएम-एजेएवाई योजना, सभी के लिए विकास सुनिश्चित करने के अपने व्यापक लक्ष्य को निम्नलिखित तीन मुख्य उद्देश्यों के माध्यम से व्यावहारिक रूप देती है: अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करके अनुसूचित जाति समुदायों की गरीबी कम करना। यह कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से किया जा सकता है। इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य आजीविका के अवसरों को बढ़ाना और लाभार्थियों को स्थायी आय सृजन गतिविधियों से जुड़ने में सक्षम बनाना है। अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा और आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार करना। यह योजना विकास संबंधी महत्वपूर्ण अंतरों को पाटने और जीवन की बेहतर गुणवत्ता में योगदान देने वाली आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच में सुधार लाने का प्रयास करती है। साक्षरता बढ़ाना और अनुसूचित जातियों को विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना। यह गुणवत्तापूर्ण संस्थानों और आवासीय विद्यालयों में पर्याप्त आवासीय सुविधाएं प्रदान करके प्राप्त किया जाता है, विशेष रूप से आकांक्षी जिलों/अनुसूचित जाति बहुल ब्लॉकों और भारत के अन्य हिस्सों में। पीएम-एजेएवाई से कौन लाभान्वित हो सकता है? पीएम-एजेएवाई के केंद्र में पात्रता का एक सुविचारित ढांचा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ उन व्यक्तियों और समुदायों तक पहुंचे, जिनके लिए यह लक्षित है। तदनुसार, योजना तक पहुंच निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर निर्धारित की जाती है: जीआईए घटक के तहत लाभार्थियों का चयन करते समय, उन परिवारों/व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है, जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। अनुसूचित जाति बहुसंख्यक समूह के अनुसूचित जाति सदस्य भी पात्र होंगे। अवसंरचना विकास के मामले में, जिन गांवों में अनुसूचित जाति की आबादी 40त्न या उससे अधिक है और कुल जनसंख्या 500 या उससे अधिक है, वे इस योजना के तहत अनुदान के लिए पात्र हैं। पीएम- एजेएवाई इन एक्शन पीएम-एजेएवाई योजना विकास के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए तीन विशिष्ट घटकों पर आधारित है: अनुसूचित जाति बहुल गांवों का आदर्श ग्राम में विकास अनुसूचित जाति बहुल गांवों को बुनियादी ढांचे और सेवाओं में मौजूद महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके आदर्श ग्राम (मॉडल गांव) में परिवर्तित करना। आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत 47,243 गांव शामिल हैं, जिससे देशभर में 47.79 लाख से अधिक नागरिकों को लाभ हुआ है। कुल 46,944 विकास कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 27,032 ग्राम विकास योजनाएं (वीडीपी) तैयार की गई हैं। 8 सितंबर 2026 तक, 18,093 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है, जो अनुसूचित जाति बहुल गांवों में बुनियादी ढांचे, मूलभूत सेवाओं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। आदर्श ग्राम वह है, जहां लोगों को विभिन्न मूलभूत सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो। समाज के सभी वर्गों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी तरह से पूरी की जाती हैं और असमानताओं को न्यूनतम स्तर तक कम किया जाता है। इन गांवों में गरिमापूर्ण जीवन के लिए ज़रुरी सभी बुनियादी ढांचे और सभी निवासियों के लिए सुलभता सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। इससे प्रत्येक निवासी को अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है। राज्य/जिला स्तर पर सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता अनुसूचित जाति (एससी) के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से जिला/राज्य स्तरीय परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसमें शामिल हैं: 1) कौशल विकास और संबंधित अवसंरचना सहित व्यापक आजीविका परियोजनाओं के माध्यम से लक्षित आबादी की आय में वृद्धि करना। 2) अनुसूचित जाति बहुल गांवों में पर्याप्त अवसंरचना का निर्माण करके सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार करना। 3) आवश्यकतानुसार आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराकर साक्षरता बढ़ाना और अनुसूचित जाति के छात्रों को विद्यालयों में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक अनुदान सहायता घटक के तहत राज्यों को सीधे ?1,730 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई है। इससे 2.5 लाख से अधिक व्यक्तिगत और समूह लाभार्थियों को कौशल विकास और आजीविका सहायता प्रदान की गई है। छात्रावासों का निर्माण/मरम्मत अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने और प्रोत्साहित करने के साधनों में से एक छात्रावासों का निर्माण और मरम्मत है। देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले छात्रों के लिए ऐसे छात्रावास अत्यंत लाभकारी हैं। सितंबर 2026 तक कुल 785 छात्र छात्रावासों का निर्माण पूरा हो चुका है। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दो छात्रावास परियोजनाओं (एक लड़कियों के लिए और एक लड़कों के लिए) के निर्माण हेतु 61.46 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता आवंटित की है, जिनसे 264 छात्रों को आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा। सशक्तिकरण में निवेश किसी भी कल्याणकारी पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निरंतर वित्तीय सहायता आवश्यक है। पीएम-एजेएवाई के अंतर्गत वित्तपोषण ढांचे का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। प्रभावी शासन की ओर एक डिजिटल छलांग हाल ही में लॉन्च किए गए पीएम-एजेएवाई मोबाइल ऐप और पीएम-एजेएवाई पोर्टल का उद्देश्य कागज आधारित कार्यप्रवाह और प्रसंस्करण से पूर्णत: डिजिटल कार्यप्रवाह और वास्तविक समय के आधार पर प्रसंस्करण की ओर परिवर्तन करना है। सुशासन पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने सार्वजनिक कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। प्रौद्योगिकी-आधारित शासन सूचना तक पहुंच में सुधार करता है, निगरानी को मजबूत बनाता है और डेटा-आधारित निर्णय लेने में सहायक होता है। यह समन्वय, पारदर्शिता और कार्यक्रम कार्यान्वयन की समग्र प्रभावशीलता को भी बढ़ाता है भारत की विकास गाथा का अगला अध्याय 2047 तक विकसित भारत की यात्रा इस सिद्धांत पर आधारित है, कि विकास के लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचने चाहिए और सभी के लिए प्रगति के अवसर सृजित करने चाहिए। इस प्रयास में, पीएम-एजेएवाई अनुसूचित जाति समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सतत आजीविका, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाले लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से इस लक्ष्य को हासिल कर रहा है। योजना के विस्तार के साथ-साथ, प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग, मजबूत निगरानी तंत्र और लक्षित अंतिम-मील वितरण इसकी प्रभावशीलता और पहुंच को बढ़ा रहे हैं। व्यक्तियों और समुदायों को उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने और भारत की विकास यात्रा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाकर, पीएम-एजेएवाई एक अधिक समावेशी, न्यायसंगत और सशक्त राष्ट्र को बढ़ावा देना जारी रखेगा।

राष्ट्र भक्ति की अलख जगाता दैनिक
राष्ट्रीय गरिमा
राष्ट्र एक बगीचा है और हम सब इसके माली
भोपाल, मंगलवार 03 नवम्बर 2026
www.rashtriyagarima.com

तीन तलाक या तलाक उल बिद्दत के प्रकार





इस्लाम में विभिन्न प्रकार के तलाक

मुस्लिम कानून के तहत तलाक की दो श्रेणियां हैं=

1. अतिरिक्त न्यायिक तलाक, और
2. न्यायिक तलाक

अतिरिक्त न्यायिक तलाक की श्रेणी को आगे तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात्,

- पति द्वारा-तलाक, इला, और जिहार।
- पत्नी द्वारा- तलाक-ए-ताफ्वेज़, लिआन।
- पारस्परिक समझौते- खुला और मुबारत द्वारा।

मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के विघटन के तहत न्यायिक तालाक देना पत्नी का अधिकार है

ट्रिपल तलाक क्या है?

ट्रिपल तलाक शब्द इस्लाम में तलाक की पद्धति को इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आम तौर पर इस शब्द का प्रयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि तीन बार तलाक कहने के बाद, जोड़ा एक साथ नहीं रह सकता है। शरिया कानून में, सामान्य तौर पर दो प्रकार के तलाक हैं=

1. तलाक अल अहसान, जो एक शब्द तलाक तीन बार कहकर किया जाता है, जो हर बार एक महीने के अंतराल पर होता है। तीसरी बार तलाक शब्द प्रयोग करने पर तलाक पूर्ण हो जाता है।
2. ट्रिपल तलाक, या तलाक उल बिद्दाट, जिसे बिना किसी अंतराल के तीन बार तलाक कह कर किया जाता है।यह तुरंत तलाक में परिणाम हो जाता है। वास्तव में, यह सबसे व्यापक रूप से अभ्यास विधि है।

भारत में तलाक-उल-बिद्दत या ट्रिपल तलाक नियम

मुस्लिम कानून के तहत तलाक पार्टियों के कार्य द्वारा या कानून की अदालत के एक डिक्री द्वारा हो सकता है। इस्लाम में, तलाक को शादी की स्थिति के अपवाद के रूप में माना जाता है। भारत में शरिया कानून के तहत एक्सप्रेस तलाक के तीन रूप हैं- अहसान तलाक, हसन तलाक (दोनों तलाक-उल-सुननाट के रूप हैं) और ट्रिपल तलाक (तलाक-उल-बिद्दत)। तलाक (मैं तालाक देता हूं) की एक घोषणा पति द्वारा पत्नी के मासिक धर्म मुक्त समय (तुहर) में किया जाता है। एक्सप्रेस तलाक के एक अन्य रूप में - हसन तलाक, पति को अपनी पत्नी की लगातार मासिक धर्म मुक्त अवधि के दौरान तीन घोषणाएं करने की आवश्यकता होती है। तीसरी घोषणा के बाद तलाक प्रभावी हो जाता है अगर इसे पहले रद्द नहीं किया गया है। और तलाक का सबसे लोकप्रिय रूप %ट्रिपल तलाक% या (तलाक-उल-बिद्दत) है। यह भी सबसे विवादास्पद है।

तलाक-उल-बिद्दत (अपरिवर्तनीय)

इस तलाक को तलक-उल-बैन भी कहा जाता है। इस तलाक की सबसे विशिष्ट विशेषता यह है कि जैसे ही शब्दों का उच्चारण किया जाता है, यह प्रभावी हो जाता है और पार्टियों के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं होती है। ट्रिपल तलाक, तलाक का एक मान्यता प्राप्त, लेकिन अस्वीकृत रूप है और इस्लामी न्यायविदों द्वारा शरिया के गुंबद के भीतर एक नवाचार के रूप में माना जाता है। यह न तो पवित्र कुरान की मंजूरी और न ही पैगंबर की मंजूरी का आदेश देता है।

तलाक-उल-बिद्दत की वैधता क्या है?

कई न्यायालय के फैसले हुए हैं जिनसे पाया गया है कि ट्रिपल तलाक अमान्य है और इसकी वैधता के लिए कुछ निश्चित आवश्यकताओं को निर्धारित किया है। मसूरु अहमद बनाम राज्य (दिल्ली का एनसीटी) [2008 (103) डीआरजे 13। (दिल्ली), ट्रिपल तलाक को एक रद्द करने योग्य तलाक माना जाता था जिसका अर्थ है कि बिद्दत को 90 दिन की प्रतीक्षा अवधि पूरी होने से पहले किसी भी समय रद्द कर दिया जा सकता है (इद्दत) जिसके बाद विवाह भंग हो जाता है। तलाक उचित कारण के लिए होना चाहिए। (क्रोध में दिया गया तलाक मान्य नहीं है)। रियाज फातिमा बनाम मोहम्मद शरीफ [200।) डीएमसी 26] में, पति को उस कारण के सबूत देना चाहिए जिन्होंने उसे तलाक लेने के लिए मजबूर किया था। इस बात का सबूत होना चाहिए की तलाक की घोषणा करते समय वहां कोई मौजूद था या कोई पत्र प्रदान किया गया हो और सुला का प्रयास करा गया हो। मेहर (दहेज) राशि का भुगतान और इद्दत (तलाक के बाद किसी महिला द्वारा प्रतीक्षा की अवधि या पति / पत्नी की मौत से पहले शादी करें) का भुगतान होना प्रमाणित होना चाहिए।

तीन तलाक भारत में क्यों माना जाता है?

जबकि कई मुस्लिम देशों ने तलाक की प्रक्रिया के मामले में अपने कानूनी कठोरता में संशोधन किया है, भारत, जहां तक इस अभ्यास का संबंध है, पुरातन मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम 1 9 3। के प्रावधानों को कायम रखने के लिए मध्ययुगीन युग में ही मानता है। यद्यपि तलाव के इस तरीके की संवैधानिक वैधता पर बहस, याचिकाएं और गड़बड़ी की लहर रही है, लेकिन धार्मिक कानून के बाद मुस्लिम, ईसाई और हिंदू समुदायों की रक्षा के देश के नियमों के कारण पुरातन कानून जारी है। भारत एक हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र होने के नाते मुस्लिम समुदाय को आश्वस्त करना है कि वह उनके साथ अन्याय नहीं कर रहा है। और मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए, भारतीय राजनीतिक नेतृत्व अपने व्यक्तिगत कानूनों को शामिल करने का जोखिम नहीं लेना चाहते। अक्सर सांप्रदायिक दंगे भारत में व्यक्तिगत कानूनों की संवेदनशीलता का उदाहरण हैं। इसके अलावा, इन कानूनों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई भी प्रयास अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और अन्य प्राधिकरणों जैसे धार्मिक बोर्डों से क्रूर विपक्ष से मिलता है, जो समर्थन करते हैं कि तीन तलाक प्रणाली में बदलाव का कोई दायरा नहीं है। उनकी विवाद यह है कि ट्रिपल तलाक का उन्मूलन कुरान की शिक्षाओं के विपरीत होगा; दूसरा, कि पुरुष निर्णय लेने में अधिक सक्षम हैं; तीसरा, वह बहुभुज, हालांकि वांछनीय नहीं है, इस्लामी है और यह वास्तव में महिलाओं को चोट पहुंचाने के बजाय मदद करता है; और चौथा, कि सुप्रीम कोर्ट को धार्मिक कानून में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

इद्दत / इदा अवधि क्या है?

पहले तलाक के बाद एक प्रतीक्षा अवधि है। इस प्रतीक्षा अवधि को इदा कहा जाता है और महिला की स्थिति (आमतौर पर तीन मासिक धर्म चक्र) पर निर्भर करता है। यह जोड़ा एक नया विवाह अनुबंध होने के बिना इस इद्दा में एकजुट हो सकता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद और जोड़ा एकजुट होना चाहता है तो एक नया विवाह अनुबंध और नया महा %होगा (दुल्हन को दुल्हन द्वारा दी गई दहेज।) अगर पति अपनी पत्नी को इस इदा के बाद वापस नहीं चाहता है, तो महिला किसी और व्यक्ति से शादी कर सकती है।

हलाला विवाह (निकाह हलाला) क्या है?

शरिया कानून के अनुसार मुस्लिम आबादी का अधिकांश हिस्सा काम करता है। शरिया इस्लाम के धार्मिक नियमों, विशेष रूप से कुरान और हदीस से ली गई है। शरिया कानून में जो जोड़ा तलाक से गुजरता है, वह तब तक पुनर्विवाह नहीं कर सकता जब तक कि महिलाएं किसी अन्य व्यक्ति से शादी न करें, शादी को समाप्त कर दें और फिर उसका दूसरा पति मर जाए या तलाक दे। इस मामले में महिलाओं के विवाह (निकाह) को उनके दूसरे पति के साथ निकाह हलाला कहा जाता है।

इस्लाम में महिलाएं तलाक कैसे दे सकती है?

भारत में मुस्लिम महिलाएं अपने पति से दो परंपरागत तरीकों से तलाक ले सकती हैं -

- एक तलाक ई ताफ्वेज़ और लिआन के माध्यम से अपने व्यक्तिगत शरिया कानून के माध्यम से होता है।
- दूसरा मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1938 के विघटन के तहत सांविधिक प्रावधान के माध्यम से। हालांकि, व्यक्तिगत शरिया कानून के माध्यम से तलाक काज़ी की जांच में होना चाहिए, जो ज्यादातर अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के नियमों के तहत निर्देशित है।

तलाक ई ताफवेज़

एक पति तलाक को किसी तीसरे पक्ष या यहां तक कि अपनी पत्नी को देने के लिए अपनी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर सकता है। वह पूरी तरह से या सशर्त रूप से, अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से शक्ति का प्रतिनिधित्व कर सकता है।सत्ता का स्थायी प्रतिनिधिमंडल रद्द कर दिया जा सकता है लेकिन सत्ता का एक अस्थायी प्रतिनिधिमंडल नहीं है। यह प्रतिनिधिमंडल उस व्यक्ति के पक्ष में स्पष्ट रूप से बनाया जाना चाहिए जिसके लिए शक्ति का प्रतिनिधि है, और प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। इस प्रतिनिधिमंडल को टैफवेज़ कहा जाता है। विवाह से पहले या उसके बाद किए गए एक समझौते से यह सुनिश्चित किया जाता है कि पत्नी को अपने पति को कुछ निश्चित शर्तों के तहत तलाक देने की स्वतंत्रता है, बशर्ते कि ऐसी शक्ति पूर्ण और बिना शर्त नहीं है और यह कि शर्तें उचित हैं और सार्वजनिक नीति का विरोध नहीं करती हैं। तलाक-ए-ताफवेज़ या प्रतिनिधि तलाक दोनों शिया और सुन्नी दोनों के बीच मान्यता प्राप्त है।

ग्रहणाधिकार

अगर पति अपनी पत्नी के खिलाफ बेईमानी या व्यभिचार के झूठे आरोपों को इंगित करता है, तो यह चरित्र हत्या की मात्रा में है और पत्नी को इन आधार पर तलाक लेने का अधिकार होगा। इस तरह के तलाक को लिआन कहा जाता है। हालांकि, यह पति द्वारा बनाई गई व्यभिचार का केवल एक स्वैच्छिक और आक्रामक आरोप है, अगर झूठी है, तो पत्नी को ग्रहणाधिकार के आधार पर तलाक का आदेश प्राप्त करने का अधिकार होगा। जहां एक पत्नी अपने पति की भावनाओं को उसके व्यवहार से पीड़ित करती है और पति उसके खिलाफ बेवफाई का आरोप वापस लेता है, तो पत्नी के बुरे व्यवहार के जवाब में पति जो कहता है, पत्नी यह सब व्यभिचार और लियानका के झूठा आरोप के तहत कोई तलाक नहीं दिया जाना चाहिए।

मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1939 का विघटन

काजी मोहम्मद अहमद काज़मी ने 1। अप्रैल 1936 को इस मुद्दे के बारे में विधायिका में एक बिल पेश किया था। हालांकि यह 1। मार्च 1939 को कानून बन गया और इस प्रकार मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 का विघटन हुआ। अधिनियम की धारा 2 इसके तहत चलती है= मुस्लिम कानून के तहत विवाहित एक महिला निम्नलिखित विवाहों में से किसी एक या अधिक पर अपने विवाह के विघटन के लिए तलाक के लिए एक डिक्री प्राप्त करने का हकदार होगा= -

- पति के ठिकाने को चार साल की अवधि के लिए जाना नहीं गया है
- पति ने उपेक्षित किया है या दो साल की अवधि के लिए रखरखाव प्रदान करने में असफल रहा है
- पति को सात साल या उससे ऊपर की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है
- पति तीन साल की अवधि के लिए उचित वैवाहिक दायित्वों के बिना, उचित कारण के बिना प्रदर्शन करने में विफल रहा है
- पति उसे क्रूरता से व्यवहार करता है

तलाक की वैधता जब मेहर वापिस नहीं दिया जाता मेहर क्या है?

मुस्लिम कानून के तहत, मेहर (दहेज) का मतलब धन या संपत्ति है जिसका विवाह विवाह के विचाराधीन पति से प्राप्त करने का हकदार है लेकिन यह विचार नागरिक अनुबंध के समान नहीं है। दहेज पति पर लगाया गया दायित्व है और गोताखोरी का उद्देश्य पत्नी को अपने विवाह के विघटन के बाद अपनी निर्वाह के लिए प्रदान करना है ताकि वह पति की मृत्यु के बाद असहाय न हो या तलाक से शादी समाप्त हो सके। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1 9 73 की धारा 125 के तहत रखरखाव की मात्रा तय करते समय मेहर को रखरखाव का हिस्सा भी माना जाता है। चूंकि डावर (मेहर) राशि के संबंध में मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक कोई स्पष्ट कटौती नहीं है, विभिन्न मामलों में भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट ने मेहर से संबंधित विभिन्न धारणाएं प्रदान की हैं।

अगर तलाक की स्थिति में पति द्वारा मेहर का भुगतान नहीं किया जाता है तो तलाव की वैधता क्या है?

मुस्लिम कानून पति और पत्नी के बीच एक अनुबंध है। और मेहर पत्नी को भुगतान करने या वादा करने का वादा किया गया है। विचाराधीन भुगतान के मामले में अनुबंध की तरह अमान्य घोषित किया जाता है। यदि मेहर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो एक तलाव को भी अमान्य माना जाता है। एक मेहर विवाहित मुस्लिम महिलाओं का अधिकार है और यदि वह अपने मेहर का भुगतान करने से इंकार कर देती है तो वह अपने पति पर मुकदमा कर सकती है।

मेहर के भुगतान के मामले में पत्नी के अधिकार क्या हैं?

- मेहर एक ऋण की तरह है और पति शादी के समापन से पहले पत्नी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। जब तक भुगतान नहीं किया जाता है, पत्नी को पति के साथ सहवास का विरोध करने का अधिकार है।
- अगर पत्नी पति की संपत्ति के कब्जे में है, तो उसे तब तक बनाए रखने का अधिकार है जब तक कि डावर का भुगतान नहीं किया जाता है। उसे संपत्ति के लिए शीर्षक नहीं मिला है और इसे अलग करने का अधिकार नहीं है।
- पत्नी पति के उत्तराधिकारी के लिए पति के वारिस मुकदमा कर सकती है।
- यदि दाता को स्थगित कर दिया गया है, तो पत्नी तलाक के कारण या मृत्यु के कारण विवाह के विघटन पर इसका हकदार है।
- डावर एक निहित अधिकार है और एक आकस्मिक अधिकार नहीं है। इस प्रकार, पत्नी की मृत्यु के बाद भी, उसके उत्तराधिकारी इसकी मांग कर सकते हैं।
- यदि विवाह के समय दहेज पर सहमति नहीं दी गई है, तो अदालतें पति की वित्तीय स्थिति, पत्नी की उम्र, जीवन की लागत, पत्नी की संपत्ति को ध्यान में रखकर गोताखोरी की राशि तय कर सकती हैं।

एक पत्नी को किस तरह के मेहर का भुगतान किया जाता है?

एक मेहर आमतौर पर दो प्रकार का होता है -

शीघ्र मेहर : इसका मतलब शादी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के समय पति द्वारा देय मेहर की कुल राशि है।

स्थगित मेहर : इसका मतलब है मेहर का वह हिस्सा जो विवाह में निर्दिष्ट पति या पति की मृत्यु के माध्यम से विवाह के विघटन के समय पत्नी को देय है। किसी भी स्थगित मेहर जो विघटन के समय अवैतनिक रहता है, वह पूर्व पति की संपत्ति के खिलाफ कर्ज बन जाता है।

क्या एक पत्नी मेहर के अपने अधिकार को छोड़ सकती है?

एक पत्नी अपने पति के पक्ष में मेहर के अधिकार को छोड़ सकती है या भेज सकती है। वह या तो प्राकृतिक प्यार से या अपने पति से स्नेह पाने के लिए ऐसा कर सकती है। इस अधिनियम को पत्नी द्वारा मेहर की छूट के रूप में जाना जाता है। पत्नी अपने निर्दिष्ट मेहर के पूरे या केवल एक हिस्से को भेज सकती है। एक कानूनी छूट के बाद, पति को मेहर के प्रेषित हिस्से को पत्नी को भुगतान करने का कोई कानूनी दायित्व नहीं है।

मुस्लिम कानून के तहत संपत्ति बंटवारा : उत्तराधिकार अधिनियम नियम और अधिकार

मुस्लिम समाज में संपत्ति का बँटवारा किसी आम कानून से नहीं, बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (मुस्लिम उत्तराधिकार अधिनियम) के नियमों से होता है। मुस्लिम उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विरासत के नियम काफी अलग हैं - जैसे इसके तहत किसी का प्रॉपर्टी पर %जन्मसिद्ध अधिकार% नहीं होता और जायदाद का बँटवारा केवल किसी की मृत्यु के बाद ही शुरू होता है। इस आर्टिकल में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ संपत्ति वितरण कानून के तहत मुस्लिमो में बेटे और बेटियों को कितना हिस्सा मिलता है, पत्नी और शौहर के क्या अधिकार हैं, और वसीयत के नियम क्या कहते हैं। साथ ही, हम यह जानेंगे कि इस्लाम धर्म में संपत्ति बाँटने से पहले किन जरूरी कामों को पूरा करना अनिवार्य है।

मुस्लिम उत्तराधिकार अधिनियम कानून

मुस्लिम कानून में जायदाद बाँटने के नियम कुरान के सिद्धांतों पर आधारित हैं। भारत में मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 लागू होता है। इस कानून की सबसे खास बात यह है कि इसमें स्व-अर्जित संपत्ति और पैतृक या पुश्तैनी संपत्ति के बीच कोई फर्क नहीं किया जाता। यानी आपने खुद कमाई हो या आपको पूर्वजों से मिली हो, बँटवारे के समय दोनों को एक जैसा ही माना जाएगा। इस्लाम धर्म में जब तक इंसान जीवित है, उसकी जायदाद में किसी का कोई हक नहीं होता। हक तभी पैदा होता है जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।

भारत में मुस्लिम कानून के तहत बंटवारे के नियम

इस्लाम के अनुसार, किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी पूरी जायदाद तुरंत वारिसों में नहीं बाँट दी जाती। पहले कुछ जरूरी जिम्मेदारियों को पूरा करना पढ़ता है :

1. कफन-दफन का खर्चा : सबसे पहले मृतक के अंतिम संस्कार का खर्चा जायदाद से निकाला जाता है।
2. कर्ज की अदायगी : अगर मृतक ने किसी से कर्ज लिया था, तो उसे चुकाना सबसे पहली प्राथमिकता है।
3. मेहर की रकम : मुस्लिम निकाह में %मेहर% एक कर्ज की तरह होता है। अगर शौहर की मृत्यु हो गई है और उसने मेहर नहीं दी थी, तो पहले पत्नी को मेहर दी जाएगी।
4. वसीयत : अगर मरने वाले ने कोई वसीयत की है, तो उसे पूरा किया जाएगा (लेकिन वसीयत केवल 1/3 हिस्से तक ही हो सकती है)।



इन सब के बाद जो बचता है, उसे ही बेटा बेटी या अन्य वारिसों के बीच विभाजित किया जाता है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ संपत्ति वितरण के तहत वारिस कितने तरह के होते हैंड़

मुस्लिम पर्सनल लॉ संपत्ति वितरण के अनुसार वारिसों को तीन मुख्य श्रेणियों में बाँटा गया है। यह तय करना बहुत जरूरी है कि कौन किस श्रेणी में आता है, क्योंकि इसी से तय होता है कि किसे हिस्सा मिलेगा और किसे नहीं।

1. निश्चित हिस्सा पाने वाले (कुरानी वारिस) ये वे लोग हैं जिनका हिस्सा कुरान में पहले से तय कर दिया गया है। जैसे पत्नी, शौहर, माँ, पिता और बेटी। इनकी कुल संख्या 12 है। सबसे पहले हिस्सा इन्हीं को दिया जाता है।
2. अवशेष वारिस जब निश्चित हिस्सा पाने वालों को उनका भाग दे दिया जाता है और उसके बाद भी जायदाद बच जाती है, तो वह अवशेष वारिसों को मिलती है। इसमें आमतौर पर बेटे शामिल होते हैं।
3. दूर के रिश्तेदार अगर ऊपर दी गई दोनों श्रेणियों में कोई भी वारिस जीवित न हो, तब जाकर जायदाद दूर के रिश्तेदारों को मिलती है।

बेटा-बेटी, पत्नी और माता-पिता के हिस्से के नियम

मुस्लिम कानून में हिस्सेदारी के नियम थोड़े अलग होते हैं, लेकिन इन्हें समझना मुश्किल नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि बेटे को बेटी से दोगुना हिस्सा मिलता है। चलिए भाषा में समझते है संपत्ति में पुत्र, पुत्री, पत्नी या शौहर को कितना हिस्सा मिलता है।

बाप की संपति पर बेटा बेटी का अधिकार

इस्लाम में बच्चों का हिस्सा सबसे प्रमुख होता है। अगर किसी के बेटे और बेटियाँ दोनों हैं, तो नियम यह है कि एक बेटे का हिस्सा दो बेटियों के बराबर होगा।

- उदाहरण के लिए : अगर किसी व्यक्ति के पास कुल 3000 रुपये बचे हैं और उसके एक बेटा और एक बेटी है। तो बेटे को 2000 रुपये मिलेंगे और बेटी को 1000 रुपये।
- तर्क : इस्लामिक विद्वानों का मानना है कि पुरुष पर पूरे परिवार की वित्तीय जिम्मेदारी (खर्चा उठाने का बोझ) होती है, जबकि महिलाओं की अपनी संपत्ति पर उनका निजी हक होता है और उनका खर्चा उठाने की जिम्मेदारी पिता, भाई या शौहर की होती है।

पत्नी और शौहर का हिस्सा

जीवनसाथी का हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि मृतक के बच्चे हैं या नहीं।

- पत्नी का हिस्सा : अगर बच्चे हैं, तो पत्नी को पूरी संपत्ति का 1/8 हिस्सा मिलता है।
- अगर बच्चे नहीं हैं, तो पत्नी को 1/4 हिस्सा मिलता है।
- अगर एक से ड्यादा पत्नियाँ हैं, तो वे इसी 1/8 या 1/4 हिस्से में बराबर की साझीदार होंगी)।
- शौहर का हिस्सा :अगर बच्चे हैं, तो शौहर को प्रॉपर्टी और जायदाद का 1/4 हिस्सा मिलता है।
- अगर बच्चे नहीं हैं, तो शौहर को 1/2 (आधा) हिस्सा मिलता है।

माता-पिता का हक

- पिता : अगर मृतक के बच्चे हैं, तो पिता को 1/6 हिस्सा मिलता है। अगर बच्चे नहीं हैं, तो वह %अवशेष वारिस% बन जाता है।
- माँ : अगर मृतक के बच्चे हैं, तो माँ को 1/6 हिस्सा मिलता है। अगर कोई बच्चा या भाई-बहन नहीं है, तो माँ को 1/3 हिस्सा मिलता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वसीयत और हिबा (गिफ्ट डीड)के नियम मुस्लिम कानून में अपनी मर्जी से जायदाद किसी को देने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं ताकि कानूनी वारिसों का हक न मारा जाए।

वसीयत के नियम

एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी पूरी जायदाद की वसीयत नहीं कर सकता।

- सीमा : वह केवल अपनी कुल जायदाद के एक-तिहाई (1/3) हिस्से की ही वसीयत कर सकता है।
- वारिस के हक में वसीयत : वह अपने किसी कानूनी वारिस (जैसे एक ही बेटे) के नाम वसीयत नहीं कर सकता, जब तक कि बाकी वारिस इसके लिए राजी न हों। यह नियम इसलिए है ताकि परिवार में झगड़ा न हो और सबको उनका जायज हक मिले।

हिबा के नियम

हिबा का मतलब है अपनी जायदाद को अपने जीवनकाल में ही किसी को तोहफे में दे देना।

- इसमें 1/3 वाला नियम लागू नहीं होता। एक व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति जीवनकाल में किसी को भी हिबा कर सकता है।
- हिबा के लिए तीन शर्तें जरूरी हैं : घोषणा , स्वीकृति , और कब्जा सौंपना।

मुस्लिम कानून और गोद लिए गए बच्चे का संपति में अधिकार

यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे लोग अक्सर सर्च करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ गोद लेने (Adoption) को मान्यता नहीं देता। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेता है, तो वह बच्चा कानूनी तौर पर उस व्यक्ति का वारिस नहीं बन सकता और उसे जायदाद में कोई हक नहीं मिलता। हालांकि, वह व्यक्ति उस बच्चे को अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा देने के लिए हिबा (उपहार) या वसीयत (जायदाद के 1/3 हिस्से तक) का इस्तेमाल कर सकता है। मुस्लिम उत्तराधिकार कानून न्याय और सुरक्षा के संतुलन पर टिका है। जहाँ यह पत्नी और माँ के अधिकारों को सुरक्षित करता है, वहीं यह भी पक्का करता है कि जायदाद परिवार के भीतर ही रहे। इन नियमों को समझकर आप भविष्य के झगड़ों से बच सकते हैं।

राष्ट्र भक्ति की अलख जगाता दैनिक
राष्ट्रीय गरिमा
राष्ट्र एक बगीचा है और हम सब इसके माली
भोपाल, मंगलवार 03 नवम्बर 2026
www.rashtriyagarima.com

अगर इजराइल में बहुमत की सरकार नहीं बनी तो नेतन्याहू बने रहेंगे पीएम?

इजराइल में चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री पद तुरंत खाली नहीं होता



यरुशलम। इजराइल में चुनाव खत्म होने के बाद भी सत्ता को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का गठबंधन सबसे बड़े गुट बन कर उभरा है, लेकिन उसके पास सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं है। वहीं विपक्षी नेता गादी आइजनकोट का गुट भी बहुमत से पीछे है। ऐसे में इजराइल में सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों का समर्थन जरूरी होगा। चुनाव के शुरुआती नतीजों के मुताबिक नेतन्याहू के गठबंधन को 120 सीटों वाली संसद में 53 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं, आइजनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गुट को करीब 48 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अरब पार्टियों के खाते में 19 सीटें जा सकती हैं। सरकार बनाने के लिए 61 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। फिलहाल किसी भी गुट के पास यह आंकड़ा नहीं हैं। चुनावों के आंशिक नतीजों के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या मौजूदा पीएम नेतन्याहू दोबारा सरकार बना पाएंगे। चुनाव में बहुमत न मिलने के बावजूद क्या नेतन्याहू अगले साल तक प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं? दरअसल, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि नई सरकार बनाने की कोशिशें कितनी जल्दी पूरी होती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल में चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री पद तुरंत खाली नहीं होता। नई सरकार बनने तक मौजूदा प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट काम करती रहती है। इसे कार्यवाहक सरकार कहा जाता है यानी चुनाव में बहुमत न मिलने के बावजूद नेतन्याहू अगले साल तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि नई सरकार बनाने की कोशिशें कितनी जल्दी पूरी होती हैं। इजराइल में चुनाव के बाद राष्ट्रपति राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत करते हैं। इसके बाद वह उस सांसद को सरकार बनाने का मौका देते हैं, जिसके पास बहुमत जुटाने की बेहतर संभावना होती है। सरकार बनाने के लिए पहले 28 दिन मिलते हैं। जरूरत पड़ने पर 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है। अगर पहला उम्मीदवार सरकार बनाने में नाकाम रहता है, तो राष्ट्रपति किसी दूसरे नेता को मौका दे सकते हैं। इसके बाद भी बहुमत नहीं जुटता, तो संसद के सदस्य किसी अन्य उम्मीदवार का नाम आगे कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कई हफ्ते लग सकते हैं। अगर तय प्रक्रिया के बाद भी कोई नेता बहुमत जुटाने में सफल नहीं होता, तो संसद भंग हो सकती है। इसके बाद नए चुनाव कराने पड़ सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है। हालांकि, कार्यवाहक सरकार का कामकाज सीमित माना जाता है। उससे बड़े नीतिगत फैसले लेने में सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। इस व्यवस्था का मकसद यह है कि देश में सरकार का कामकाज पूरी तरह ठप न हो। इसलिए इजराइल में चुनाव के बाद भी नेतन्याहू की प्रधानमंत्री पद पर मौजूदगी बनी रह सकती है।



मैक्सिको के सेंटा मारिया में ड्रोन से ली गयी एक तस्वीर में लोग अपने करीबियों के स्मारकों पर नजर रखते हुए।

नेतन्याहू की सत्ता पर संकटः अरब पार्टियों के समर्थन से पलटेगा राजनीतिक समीकरण

दोनों अरब पार्टियां गादी आइसेनकोट के गुट को समर्थन देने को तैयार

तेल अवीव (ईएमएस)। इजराइल की राजनीतिक गलियों में सत्ता परिवर्तन की तेज सुगबुगाहट है, जहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। विपक्षी गुट को दो प्रमुख अरब पार्टियों का समर्थन मिलने की संभावना है, इससे नेतन्याहू के लिए राजनीतिक मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। हालिया चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, इसके बाद नई सरकार के गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इस बीच, दो प्रमुख अरब पार्टियों, राआम और जॉइंट लिस्ट ने नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए पूर्व सेना प्रमुख गादी आइसेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गुट को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। इन दोनों पार्टियों के पास संसद में कुल 19 सीटें हैं, जो किसी भी गठबंधन के लिए निर्णायक साबित हो सकती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जॉइंट लिस्ट ने स्पष्ट किया है कि वह नेतन्याहू विरोधी पार्टियों को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार है, हालांकि वह स्वयं सरकार में शामिल नहीं होगी। जॉइंट लिस्ट के सांसद अहमद तिबी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे हर उस प्रयास का हिस्सा बनना चाहते हैं जो मौजूदा सरकार को गिराकर एक नई और उम्मीद भरी सरकार बनाए। अरब राजनीतिक आंदोलन के प्रमुख जाफर फराह ने पुष्टि की है कि राआम और जॉइंट लिस्ट, दोनों इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग को गादी आइसेनकोट को अगले प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तावित करने के लिए अपना समर्थन देने को तैयार हो सकती हैं। यदि ऐसा होता है, तब नेतन्याहू के सामने अपनी सत्ता बचाने की एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। सांसद अहमद तिबी ने आइसेनकोट से दिवंगत प्रधानमंत्री यित्जाक राबिन की तरह बनने का आग्रह किया है। राबिन 1993 के ओस्लो समझौते के लिए मशहूर हैं, जिसके तहत इजराइल ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के साथ ऐतिहासिक बातचीत शुरू की थी। तब भी, राबिन के इस साहसिक फैसले की व्यापक आलोचना हुई थी, लेकिन दो अरब नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टियों ने बाहर से उनकी सरकार को समर्थन दिया था।

संक्षिप्त समाचार

बुगाटी के सीईओ की 25 करोड़ की कार कैंपस से चोरी, पोर्शे से पीछा कर पकड़ा

ज़ाग्रेब। लक्ज़री सुपरकार निर्माता बुगाटी के सीईओ मेट रिमैक की करीब 25 करोड़ रुपए की बुगाटी शिरॉन कार कंपनी कैंपस से ही चोरी हो गई। यह सनसनीखेज वारदात क्रोएशिया की राजधानी ज़ाग्रेब के पास बुगाटी के उत्पादन परिसर में हुई, जिसके बाद सीईओ मेट रिमैक ने खुद अपनी पोर्शे 911 से चोर का पीछा किया और उसे पकड़वाने में मदद की। जानकारी के मुताबिक मेट रिमैक अक्सर अपनी महंगी गाड़ियों में चाबी अंदर ही छोड़ देते थे, ताकि कर्मचारी उन्हें आसानी से इधर-उधर ले जा सकें। बुधवार को कंपनी कैंपस में नौकरी तलाशने आया 35 साला का एक युवक कार में चाबी देखकर उसे स्टार्ट कर फरार हो गया। मेट रिमैक ने बाद में बताया कि क्रोएशिया के सुरक्षित माहौल के कारण वे सालों से ऐसा कर रहे थे, लेकिन अब इस घटना के बाद वे भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे कैंपस में हड़कंप मच गया। चोरी की खबर मिलते ही मेट रिमैक ने बिना देर किए अपनी पोर्शे 911 कार निकाली और तेजी से आरोपी का पीछा किया। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी और बुगाटी शिरॉन के हाई-टेक टेलीमेट्री सिस्टम से कार को ट्रैक किया। कार पड़ोसी देश स्लोवेनिया की तरफ तेज रफ्तार में बढ़ रही थी। रिमैक ने पुलिस अधिकारियों के साथ एक ग्रुप बनाया और उसमें कार की लाइव लोकेशन लगातार साझा की। इस सटीक जानकारी की मदद से ऑस्ट्रिया की पुलिस ने सीमा पार करते ही आरोपी को चारों तरफ से घेरकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मेट रिमैक ऑस्ट्रिया के पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां पकड़े गए युवक से बात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक युवक ने बताया कि वह नौकरी की तलाश में आया था और चाबी देखकर कार लेकर भाग निकला। इस भागदौड़ में कार को थोड़ा नुकसान पहुंचा है जिसकी मरम्मत कराई जाएगी।

सऊदी गठबंधन ने हूती के अहम संसाधनों को तबाह करने का किया दावा

रियाद। यमन में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा है कि उसने हूती गुट के अहम संसाधनों को निष्क्रिय करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है। गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल-मल्की ने एक्स पर एक बयान जारी कर कहा कि अभियान रविवार सुबह चलाया गया। यह कदम सऊदी अरब और यमन में नागरिकों और नागरिक ठिकानों पर हूती विद्रोहियों के लगातार हमलों के जवाब में उठाया गया था। अल-मल्की ने बताया कि हूती विद्रोही इन संसाधनों का इस्तेमाल अपने युद्ध प्रयासों को समर्थन देने और अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कर रहे थे, खासकर अपने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों के लिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस अभियान की जगह या इसके नतीजों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। इसके अलावा रविवार को यमन के दक्षिणी बंदरगाह शहर अदन में स्थानीय निवासियों और एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि शहर में एक सरकारी सैन्य ठिकाने के पास हूती मिसाइल गिरी, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि मिसाइल पश्चिमी अदन के अल-बुरैका जिले में उस सैन्य ठिकाने के पास गिरी, जिसका इस्तेमाल सऊदी समर्थित यमनी सरकारी सेना कर रही थी। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अदन जो यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का अस्थायी मुख्यालय है, हाल के दिनों में हूती विद्रोहियों द्वारा किए जा रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों की चपेट में आ गया है। यमन 2014 के आखिर से ही संघर्ष में उलझा हुआ है। उस समय हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना और उत्तरी यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमनी सरकार के समर्थन में हस्तक्षेप किया। एक बयान में हूती समूह के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने मक्का के ऊपर ड्रोन रोके जाने के सऊदी अरब के दावे को खारिज करते हुए इसे झूठा बताया। सरिया ने कहा कि उनके समूह ने सऊदी अरब के क्षेत्र की ओर कोई अभियान नहीं चलाया।

ट्रंप की चेतावनी : ईरान के एक-दो परमाणु ठिकानों से अभी निपटना बाकी

वाशिंगटन। पश्चिम एशिया में जारी भारी कूटनीतिक और सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी ने अंतरराष्ट्रीय जगत में फिर हड़कंप मचा दिया है। फ्लोरिडा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि ईरान के एक-दो परमाणु ठिकानों से अभी निपटना बाकी है। उन्होंने नतांज परमाणु केंद्र के पास स्थित पिकएक्स माउंटेन का नाम लेते हुए कहा कि इस स्थान को अमेरिकी सेना निशाना बना सकती है। इस बयान के बाद यह सवाल गहरा गया है कि आखिर इस विशालकाय पहाड़ के अंदर ईरान का क्या रहस्य छिपा है, जिससे अमेरिका आशंकित है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिकएक्स माउंटेन ईरान के इस्फहान प्रांत में स्थित एक विशाल चट्टानी पहाड़ी क्षेत्र है, जिसे कूह-ए कोलांग गज ला कहा जाता है। यह स्थान ईरान के सबसे प्रमुख यूरेनियम संवर्धन केंद्र नतांज से दो किलोमीटर दक्षिण में और तेहरान से करीब 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ठोस ग्रेनाइट पहाड़ के अंदर ईरान ने गहरी और मजबूत सुरंगों का एक बेहद जटिल नेटवर्क तैयार किया है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस भूमिगत परिसर का निर्माण अपने सबसे संवेदनशील यूरेनियम संवर्धन और सेंट्रीफ्यूज विनिर्माण इकाइयों को बाहरी हवाई हमलों से पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए कर रहा है। उपग्रह से प्राप्त ताजा तस्वीरों के विश्लेषण से पता चलता है कि पहाड़ के अंदर प्रवेश करने वाले मुख्य द्वारों पर फिलहाल मिट्टी के बड़े अवरोध लगाए गए हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय रक्षा विश्लेषकों और इजराइली खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इस दुर्गम परिसर के अंदर अत्याधुनिक सेंट्रीफ्यूज उपकरण और संवर्धित यूरेनियम की खेप पहले ही पहुंचाई जा चुकी है। अमेरिकी रक्षा रणनीतिकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह ठिकाना जमीन से काफी गहराई में और कठोर चट्टानों के बीच बना है।

नेपाल में 3,600 मीटर की ऊंचाई पर फंसे छह भारतीय पर्यटक, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू शुरू

काठमांडू। नेपाल के अत्यंत दुर्गम और सुदूर हिमालयी क्षेत्र में स्थित शे-फोक्सुंडो राष्ट्रीय उद्यान में मौसम के अचानक बिगड़ने और भारी बर्फबारी के कारण दो महिलाओं समेत छह भारतीय पर्यटक फंस गए हैं। समुद्र तल से करीब 3,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शे-फोक्सुंडो झील का दीदार करने पहुंचे ये सभी पर्यटक शून्य से नीचे गिरते तापमान और चारों ओर जमी बर्फ की मोटी चादर के बीच अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और नेपाली सुरक्षा बल खराब मौसम के बावजूद सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रहे हैं। डोल्पा जिले के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जुनु ढकाल द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक यह सभी भारतीय नागरिक शे-फोक्सुंडो ग्रामीण नगरपालिका के धो इलाके में ट्रेकिंग और पर्यटन के उद्देश्य से पहुंचे थे। यह पूरा इलाका नेपाल की सबसे गहरी शे-फोक्सुंडो झील के पास पड़ता है, जो अपने असीम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। 31 अक्टूबर की दोपहर से ही पूरे पर्वतीय इलाके में मूसलाधार बर्फबारी हो रही थी, जिससे रास्ते पूरी तरह बंद हो गए और दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई।

राष्ट्रपति योतोवा की जीत की संभावना बनी, 52 फीसदी मत मिलने का अनुमान

सोफिया। बुल्गारिया में राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण के बाद आए 'एग्जिट पोल' के नतीजों के मुताबिक मौजूदा राष्ट्रपति इलियाना योतोवा की जीत की संभावना है। आधिकारिक आंशिक परिणाम जल्द जारी होने की उम्मीद है। 'एग्जिट पोल' में योतोवा को करीब 52 फीसदी मत मिलने का अनुमान जताया गया है। यदि आधिकारिक परिणामों में इसकी पुष्टि होती है, तो वह बुल्गारिया की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्र प्रमुख बन जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुधारवादी और पश्चिम समर्थक विपक्षी दलों के समर्थन वाले पूर्व अंतरिम प्रधानमंत्री आंद्रेई ग्युरोव लगभग 44 फीसदी मतों के साथ पीछे हैं।

इजराइल चुनावः पीएम नेतन्याहू चुनाव नतीजों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे : गादी

तेल अवीव। इजराइल में चुनाव के बाद विपक्षी नेता गादी आइजनकोट सरकार बनाने की कोशिशों में जुट गए हैं। उन्होंने डेमोक्रेट्स पार्टी के प्रमुख यायर गोलान, बियाचाद के प्रमुख नफ्ताली बेनेट और विपक्षी नेता यायर लैपिड से मुलाकात की। आइजनकोट ने आरोप लगाया कि पीएम नेतन्याहू और उनकी लिकुड पार्टी चुनाव नतीजों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुमत नहीं मिला है। चुनाव में अब तक आइजनकोट के गठबंधन को 48 सीटें मिली हैं, जबकि नेतन्याहू खेमे को 53। वहीं अरब पार्टी ने 19 सीटें मिली हैं। इजराइल की संसद में कुल 120 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 61 सीटों का समर्थन जरूरी है। ऐसे में किसी भी खेमे के पास बहुमत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल में सभी वोटों की गिनती के बाद जॉइंट लिस्ट गठबंधन को 11 सीटें मिली हैं। यह इजराइल की अरब आबादी के अधिकारों की बात करने वाला राजनीतिक गठबंधन है। इसमें तीन अलग-अलग पार्टियां शामिल हैं। गठबंधन में अरब नेताओं के साथ यहूदी नेता भी हैं। हदाश यह वामपंथी पार्टी है। यह अरब और यहूदी नागरिकों की समानता, मजदूरों के अधिकारों और फिलिस्तीन के साथ शांति की वकालत करती है। ताल यह अहमद तिबी की पार्टी है। यह अरब नागरिकों के समान अधिकार, शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसरों और फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का समर्थन करती है। बलद यह अरब राष्ट्रवादी विचारधारा वाली धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। यह इजराइल को ऐसा देश बनाने की वकालत करती है, जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलें। नेतन्याहू के सहयोगी दल यूनाइटेड टोरा जूडिज्म ने विपक्षी नेता गादी आइजनकोट को प्रधानमंत्री पद देने का प्रस्ताव दिया है। पार्टी इसके बदले हरेदी यहूदियों को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट देने की मांग कर रही है।

बांग्लादेश में भड़की श्रमिकों की हिंसा : वेतन वृद्धि की मांग पर अड़े, कारखाने बंद

ढाका। बांग्लादेश में बेहतर वेतन की मांग को लेकर हजारों गारमेंट मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद राजधानी ढाका और गाजीपुर में व्यापक हिंसा भड़क उठी। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एक गाड़ी को आग के हवाले किया और सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 19 लोगों को हिरासत में लिया है। मजदूरों की मुख्य मांग है कि उनका न्यूनतम मासिक वेतन बढ़ाकर 30 हजार बांग्लादेशी टका, जो करीब 23 हजार भारतीय रुपये के बराबर है, किया जाए। प्रदर्शनों के दौरान गाजीपुर में मजदूरों ने ढाका-टांगाइल हाईवे को जाम कर दिया, जिससे जनजीवन और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) की पांच प्लाटून तैनात की गईं। ढाका के मीरपुर इलाके में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई भीषण झड़प के बाद पुलिस वाहन को आग के हवाले किया गया। मीरपुर डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर हसन मोहम्मद नाशेर रिकाबदार ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ पुलिस वाहन जलाने और पुलिसकर्मियों पर हमले के कई मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। गाजीपुर में हिंसा इतनी बढ़ गई कि कपड़े के कचरे से भरे एक फैक्ट्री गोदाम और एक पिकअप वैन में भी आग लगा दी गई।

चीन के झांग शुए ने पानी पर दौड़ाई मोटरसाइकिल, बनाया नया विश्व रिकॉर्ड



बीजिंग। चीन के उद्यमी, झांग शुए ने अविश्वसनीय कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने अपनी विशेष रूप से संशोधित बाइक को पानी पर 40.74 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलाकर नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह हैरतअंगेज उपलब्धि उन्होंने 25 अक्टूबर को अपने गृहनगर हुनान प्रांत के हुआइहुआ शहर में दर्ज की, जिसने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है। 39 वर्षीय झांग शुए, जो चीन की प्रसिद्ध मोटरसाइकिल कंपनी ज़ीएक्समोटो के संस्थापक भी हैं, ने रिकॉर्ड को बनाने के लिए एमएक्स 450 मॉडल की विशेष रूप से तैयार की गई बाइक का इस्तेमाल किया। उन्होंने खुले पानी में मोटरसाइकिल से सबसे लंबी दूरी तय करने का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो 31.8 किलोमीटर का था। झांग ने पानी की सतह पर सफलतापूर्वक 40.74 किलोमीटर की दूरी तय की, जो उनकी इंजीनियरिंग कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। उनके इस असाधारण प्रदर्शन को देखकर मौके पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। एक सामान्य बाइक का पानी पर चलना करीब असंभव लगता है, लेकिन झांग ने अपनी बाइक में कई महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव कराए थे। रिपोर्ट के अनुसार, इसमें विशेष फ्लोटिंग पार्ट्स लगाए गए थे जो बाइक को पानी में डूबने से बचाते थे। इसके साथ ही, बाइक के महत्वपूर्ण हिस्सों को पूरी तरह से वॉटरप्रूफ बनाया गया था ताकि पानी के संपर्क में आने के बावजूद उसका संचालन सुचारू रूप से चलता रहे। इस चुनौतीपूर्ण अभियान के दौरान सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया था, झांग के साथ रेस्क्यू बोट और एक मेडिकल टीम भी मौजूद थी। उन्होंने नदी में निर्धारित मार्ग के छह चक्कर पूरे किए, जिसमें शारीरिक थकान और मुश्किल मोड़ भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा। बात दें कि झांग को सफलता रातोंरात नहीं मिली। उन्होंने करीब 22 साल की उम्र में पहली बार पानी पर बाइक चलाने का सपना देखा था। अपने सपने को साकार करने के लिए उन्होंने शुरुआती दौर में चार बार प्रयास किए, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही मिली। उनकी सबसे लंबी कोशिश में बाइक सिर्फ 20 मीटर तक ही पानी पर चल सकी थी। हालांकि, झांग ने हार नहीं मानी और इस बार रिकॉर्ड बनाने के लिए अपनी टीम के साथ करीब पाँच महीने तक कड़ी तैयारी की। इस दौरान बाइक के फ्लोटिंग सिस्टम, वॉटरप्रूफ सील और पावर सिस्टम में कई सुधार किए गए, और पानी में बार-बार परीक्षण कर बाइक को स्थिर व सुरक्षित बनाया गया। गिनीज विश्व रिकॉर्ड्स के अधिकारियों ने जीपीएस डेटा, समय और वीडियो फुटेज की विस्तृत जांच के बाद उनके रिकॉर्ड को आधिकारिक मान्यता दी। झांग ने अपनी सफलता पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा अपने काम पर विश्वास था और यह रिकॉर्ड उन्होंने अपने गृहनगर हुआइहुआ को भी दुनिया भर में पहचान दिलाने के उद्देश्य से बनाया है।

जॉर्जिया राज्य में भारतीय मूल की महिला फोर्सिथ काउंटी कमिश्नर पद के लिए मैदान में

कमिंग। अमेरिका में जॉर्जिया राज्य में भारतीय मूल की अमेरिकी महिला स्थानीय नेतृत्व के एक अप्रत्याशित चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं, जहां कभी श्वेत लोगों की नस्ली श्रेष्ठता में विश्वास रखने वाले संगठन कू क्लक्स क्लान (केकेके) का दबदबा था और नस्लवाद जीवन का हिस्सा था। भारतीय-अमेरिकी महिला यह चुनाव इसलिए लड़ना चाहती है क्योंकि वह अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी की 'धौंस' के आगे झुकने के बजाय उसका सामना करना चाहती हैं और बच्चों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़कर जाना चाहती हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेट शुचिता पटेल 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव में फोर्सिथ काउंटी कमिश्नर के पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। इस काउंटी का नस्ली हिंसा का भयावह इतिहास रहा है। वर्ष 1912 में श्वेत निवासियों और नस्ली श्रेष्ठता में विश्वास रखने वाले केकेके गिरोहों ने करीब पूरी अश्वेत आबादी को जबरन यहां से खदेड़ दिया था। इसके बाद 20वीं सदी के अधिकांश समय तक यह काउंटी पूरी तरह श्वेत आबादी वाला क्षेत्र बनी रही।

अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में भारतीय मूल के उम्मीदवारों की रिकॉर्ड भागीदारी

वाशिंगटन। अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य में भारतीय समुदाय के बढ़ते प्रभाव का स्पष्ट संकेत है। मंगलवार को होने वाले मतदान में कुल 57 भारतीय-अमेरिकी चेहरे अपनी किस्मत आजमाएंगे, जो सीनेट से लेकर गवर्नर, मेयर और राज्य विधानमंडल तक विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। यह संख्या अमेरिकी समाज में भारतीय-अमेरिकी समुदाय की बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षा और परिपक्वता को रेखांकित करती है। इन 57 उम्मीदवारों में से एक सीनेट, 11 प्रतिनिधि सभा, तीन राज्यव्यापी पदों, 36 राज्य विधानमंडलों और छह स्थानीय पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ प्रमुख मुकाबलों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओहायो में रिपब्लिकन पार्टी के विवेक रामास्वामी गवर्नर पद के लिए अपनी उम्मीदवारी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, और उनकी जीत भारतीय मूल के नेताओं की स्थिति को नई ऊंचाई दे सकती है। लॉस एंजिलिस में सिटी काउंसिल सदस्य नित्या रमन मौजूदा मेयर को चुनौती दे रही हैं, जहां मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। न्यूयॉर्क में सरिता कोमाटिरेड्डी अटॉर्नी जनरल के पद के लिए मैदान में हैं, वहीं मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणा मिलर दोबारा चुनाव जीतने की कोशिश में हैं। मैसाचुसेट्स की सीनेट सीट पर शिवा अय्यादुरई एकमात्र भारतीय मूल के उम्मीदवार के रूप में निर्दलीय दावेदारी पेश कर रहे हैं। प्रतिनिधि सभा के चुनावों में भी भारतीय मूल के नेताओं की मजबूत उपस्थिति है। इनमें कैलिफोर्निया से रो खन्ना और अमी बेरा, वाशिंगटन राज्य से प्रमिला जयपाल और वर्जीनिया से सुहास सुब्रमण्यम जैसे चार मौजूदा डेमोक्रेटिक सांसद शामिल हैं। इस बार कुछ दिलचस्प मुकाबले भी हैं, जहां भारतीय मूल के उम्मीदवार आमने-सामने हैं।

राष्ट्र भक्ति की अलख जगाता दैनिक
राष्ट्रीय गरिमा
राष्ट्र एक बगीचा है और हम सब इसके माली
भोपाल, मंगलवार 03 नवम्बर 2026
www.rashtriyagarima.com

कोलंबो में टेस्ट ट्वेंटी: क्रिकेट में लैंगिक समानता की नई मिसाल करेगा पेश



कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 14 नवंबर से क्रिकेट इतिहास का एक अभूतपूर्व अध्याय लिखा जाने वाला है, जब टेस्ट ट्वेंटी नामक एक अनूठा क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होगा। यह प्रतियोगिता क्रिकेट जगत में पहली बार लड़कों और लड़कियों को एक ही टीम में खेलते हुए देखेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य खेल में लैंगिक समानता और सहभागिता को बढ़ावा देना है। 14 से 29 नवंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में हार और जीत का फैसला खिलाड़ियों के संयुक्त प्रदर्शन और उनके द्वारा बनाए गए साझा रनों के आधार पर होगा। यह पहल 13 से 21 वर्ष की आयु के 160 युवा क्रिकेटरों को एक ऐसा मंच प्रदान करेगी, जहाँ प्रतिभा और टीम वर्क लिंग भेद से ऊपर होगा। इस टूर्नामेंट की सबसे खास बात इसकी मिश्रित टीम संरचना है। खिलाड़ियों को चार महाद्वीपीय टीमों में बांटा जाएगा, जिनमें से प्रत्येक टीम में 20 लड़कियां और 20 लड़के होंगे, जिससे हर टीम में कुल 40 खिलाड़ी शामिल होंगे। यह ढांचा मैदान पर पूर्ण समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है, जहां हर खिलाड़ी का योगदान टीम के समग्र प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण होगा। टूर्नामेंट के संस्थापक गौरव बहिरवानी के अनुसार, समानता सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रसारण के दौरान भी लड़कों और लड़कियों को बराबर कवरेज देने की योजना है, ताकि उनकी उपलब्धियों को समान रूप से सराहा जा सके। यह क्रिकेट के जरिए सामाजिक बदलाव लाने की एक महत्वपूर्ण कोशिश है। कोलंबो के प्रतिष्ठित सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट का टेस्ट ट्वेंटी प्रारूप भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। प्रत्येक मुकाबला एक ही दिन में पूरा होगा और कुल 80 ओवरों का खेल खेला जाएगा। शुरुआती 40 ओवर दिन के समय लाल गेंद से सफेद पोशाक में खेले जाएंगे, जिसके बाद बाकी 40 ओवर सफेद गेंद से रंगीन पोशाक में फ्लडलाइट की रोशनी के बीच आयोजित होंगे। दोनों चरणों में बनाए गए रन टीम के कुल स्कोर में जोड़े जाएंगे, और प्रत्येक टीम को दो बार बल्लेबाजी करने का अवसर मिलेगा, जिससे खेल में रोमांच और रणनीति का समावेश होगा। यह दोहरी प्रकृति खेल में रणनीतिक गहराई और रोमांच का संचार करेगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को क्रिकेट जगत के कई दिग्गजों का भी भरपूर समर्थन प्राप्त है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन और वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी क्लाइव लॉयड इसके सलाहकार बोर्ड में शामिल हैं, जो टूर्नामेंट की विश्वसनीयता और महत्व को बढ़ाते हुए इसे वैश्विक पहचान प्रदान करते हैं। भारतीय क्रिकेट कोच राजकुमार शर्मा वैश्विक चयन समिति की अध्यक्षता करेंगे, जबकि संचालन की जिम्मेदारी माइक फोर्डहम को सौंपी गई है।

मुकेश के पांच विकेटों के बाद भी न्यूजीलैंड-ए ने भारत-ए पर बनाई बढ़त

लिंकन। न्यूजीलैंड-ए ने यहां भारत ए के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे अनधिकृत टेस्ट के तीसरे दिन बढ़त हासिल कर ली। भारतीय टीम की ओर से तेज़ गेंदबाज़ मुकेश कुमार ने शुरुआत मे पांच विकट लेकर मेजबानों पर दबाव बनाया था लेकिन उसके निचले क्रम के बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन कर स्थित संभाल ली। उसके बल्लेबाजों ने दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी मे 424 रन बनाये। जवाब में भारत ए ने दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 32 रन बना लिए हैं। भारत ऐ टीम ने पहली पारी मे 346 रन बनाये थे। खेल के तीसरे दिन न्यूजीलैंड-ए ने अपनी पहली पारी में 3 विकेट पर 218 रनों से आगे खेलना शुरु किया। उस समय इंडिया-ए के पास 128 रनों की मजबूत बढ़त मौजूद थी, और भारतीय खेमा इस बढ़त को और बढ़ाने के लिए उत्सुक था। नई गेंद मिलते ही भारतीय गेंदबाज़ों ने आक्रामक रुख अपनाया और शुरुआती झटके देकर कीवी बल्लेबाज़ों पर दबाव बनाया। मुकेश कुमार ने विशेष रूप से शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बल्लेबाज़ क्रिस्टन क्लार्क को 41 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके न्यूजीलैंड-ए को आठवां झटका दिया और इसी के साथ अपने पांच विकेट पूरे किए। मोहम्मद सिराज ने भी अपनी सटीक लाइन और लेंथ से कीवी बल्लेबाज़ों को काफी परेशान किया, जिससे लंच ब्रेक तक भारतीय टीम की स्थिति मजबूत लग रही थी। लंच तक न्यूजीलैंड का स्कोर 7 विकेट पर 291 रन था और भारत के पास अभी भी 53 रनों की बढ़त बची हुई थी। हालांकि, लंच के बाद मुकाबले का रुख पूरी तरह से बदल गया। न्यूजीलैंड-ए के निचले क्रम के बल्लेबाज़ों ने, खासकर अंतिम जोड़ी के रूप में क्रीज़ पर उतरे जैरोड मैके और लेननॉक्स ने भारतीय गेंदबाज़ों की सभी योजनाओं पर पानी फेर दिया। इन दोनों ने धैर्यपूर्वक और सूझबूझ भरी बल्लेबाज़ी करते हुए न केवल अपनी टीम का स्कोर 350 रनों के आंकड़े के पार पहुंचाया, बल्कि भारत-ए पर निर्णायक बढ़त भी हासिल कर ली।

प्रशांत वीर को रिलीज कर सकती है सीएसके

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2027 के लिए होने वाले बड़ी नीलामी से पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) अपने स्पिन ऑलराउंडर प्रशांत वीर को रिलीज कर सकती है। सीएसके ने प्रशांत को आईपीएल 2026 में ?14.20 करोड़ की मोटी कीमत पर खरीदा गया था पर उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, जिसके चलते टीम को यह कड़ा निर्णय लेना पड़ रहा है और उनका यह महंगा दांव विफल साबित हुआ है। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार, सीएसके ने आईपीएल के पिछले सत्र में प्रशांत बड़ी उम्मीद के साथ अपनी टीम में शामिल किया था पर वह विफल रहे। इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद भी उनका प्रदर्शन टीम की अपेक्षाओं के बिल्कुल अनुरूप नहीं रहा। आंकड़ों पर गौर करें तो, आईपीएल 2026 में प्रशांत वीर ने सीएसके के लिए केवल 6 मैच खेले, जिसकी 5 पारियों में वे सिर्फ 90 रन बना सके। उनकी बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी भी अच्छी नहीं रही। वह पूरे सत्र में एक भी विकेट नहीं ले पाये। यह प्रदर्शन उनकी बड़ी कीमत और टीम की उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत था, जिससे फ्रेंचाइजी को काफी निराशा हुई है और इसी वजह से सीएसके ने उन्हें रिलीज करने का मन बना लिया है। गौरतलब है कि अनुभवी स्पिनर रविंद्र जडेजा के टीम से जाने के बाद से सीएसके को एक मजबूत स्पिन ऑलराउंडर की कमी खल रही थी। प्रशांत को इसी महत्वपूर्ण भूमिका को भरने और टीम के लिए भविष्य के एक अहम खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा था। आईपीएल 2026 से पहले, प्रशांत ने उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट में अपने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया था, जिसने सीएसके को उन पर इतनी बड़ी बोली लगाने के लिए प्रेरित किया। उस समय उन्हें टीम के भविष्य के स्तंभ के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन आईपीएल जैसे बड़े मंच पर वह अपनी क्षमता को दोहराने में विफल रहे, जिससे टीम को मजबूरन यह कड़ा फैसला लेना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि प्रशांत वीर को रिलीज करने के बाद, चेन्नई सुपर किंग्स गोवा में होने वाले आगामी नीलामी में उन्हें कम कीमत पर फिर से खरीद सकती है।

ऑस्ट्रेलियाई ने इंग्लैंड के खिलाफ एकदिवसीय और टी20 सीरीज के लिए घोषित की टीम

सिडनी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए अपनी एकदिवसीय और टी20 टीमों टीम घोषित कर दी है। सीए ने घरेलू मैदानों पर होने वाली इस सीरीज के लिए तीन प्रमख तेज गेंदबाजों को आराम देते हुए युवाओं को अवसर दिया है। मिचेल मार्श की कप्तानी में घोषित इन टीमों में कई बड़े बदलाव किये गये हैं। इसमें तीन प्रमुख और अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ों पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेज़लवुड—को शामिल नहीं किया गया है। यह फैसला दिसंबर से शुरू हो रहे 10 टेस्ट मैचों के व्यस्त और थकाऊ शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। चयनकर्ताओं का मानना है कि इन प्रमुख गेंदबाज़ों को तरोताजा और पूरी तरह फिट बनाए रखने के लिए आराम दिया गया है ताकि वे आगामी टेस्ट सीरीज के लिए तैयार रहें। सीनियर गेंदबाज़ों की अनुपस्थिति में चयनकर्ताओं को युवा प्रतिभाओं पर भरोसा जताया है। एकदिवसीय टीम में पहली बार युवा तेज़ गेंदबाज़ महली बियर्डमैन और प्रतिभाशाली बल्लेबाज़ ऑली पीक को शामिल किया गया है। इनके साथ ही, ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स और लियाम स्कॉट को भी एकदिवसी स्क्वाड में जगह मिली है। वहीं टी20 टीम मे निखिल चौधरी, जोएल डेविस, बियर्डमैन और एडवर्ड्स को शामिल किया गया है, जबकि विकेटकीपर लैकलान शॉ और सैम हार्पर को अनकैप्ड खिलाड़ियों के रूप में पहली बार राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है। वहीं कुछ अनुभवी खिलाड़ियों की एकदिवसीय टीम में वापसी हुई है। इसमें ट्रैविस हेड, मैथ्यू रेनशॉ, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी, जोश इंग्लिस और कूपर कॉनोली शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एकदिवसी सीरीज़ की शुरुआत 13 नवंबर को पर्थ में होगी, जिसके बाद एडिलेड और होबार्ट में बाकी दो मैच खेले जाएंगे। इसके बाद 21 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ का आयोजन मेलबर्न, गोल्ड कोस्ट, ब्रिसबेन, सिडनी और कैनबरा जैसे प्रमुख स्थानों पर किया जाएगा।

हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी : भारतीय हॉकी टीम मलेशिया को हराकर शीर्ष पर बरकरार

मोहाली। भारतीय हॉकी टीम ने यहां जारी हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हुए मलेशियाई टीम को 4-2 से हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने राउंड रॉबिन स्टेज की अंक तालिका में अपना नंबर एक स्थान और पक्का कर लिया है। भारतीय टीम के अब चार मैचों में 12 अंक हो गए हैं, जबकि मलेशियाई टीम नौ अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। इस मुकाबले से पहले दोनो ही टीमें बराबरी पर थीं। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक आठ गोल किये हैं और वह अब तक सबसे गोल करने वालों में नंबर एक पर हैं। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अब तक चार मुकाबलों में कुल 26 गोल दागे हैं, जो उसकी गोल करने की असाधारण क्षमता को दर्शाता है। वहीं, 21 के प्रभावशाली गोल अंतर के साथ भारत अंक तालिका में मजबूती से पहले स्थान पर बना हुआ है, जो उसके बेहतरीन खेल और संतुलन का प्रतीक है।

वहीं एक अन्य मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने बांग्लादेश को 5-0 से हराया। यह कोरियाई टीम की टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले उसने चीन को हराया या। इस जीत के बाद कोरिया के चार मैचों में छह अंक हो गए हैं, जिससे उसकी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें काफी मजबूत हुई हैं। वहीं, चीन और जापान के बीच खेला गया मुकाबला 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने पूरे मैच में शानदार खेल दिखाया और दो-दो गोल किए, लेकिन कोई भी टीम निर्णायक बढ़त हासिल नहीं कर सकी। जापान इस मुकाबले में भारत के खिलाफ मिली हार के बाद वापसी के इरादे से उतरा था और अपनी पिछली निराशा को पीछे छोड़ना चाहता था, जबकि चीन टूर्नामेंट में अपने पहले अंक की तलाश कर रहा था। इस ड्रॉ से दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला।



न्यूयार्क में सिटी मैराथन में जीत के बाद उत्साहित होती हुई केन्या की शैला शीपुकिराई, जैसिका मैककलेन। व हैलन उबरी।

व्यापार समाचार

संक्षिप्त समाचार

नवंबर में निवेश के दो नए द्वार, डेट फंड से चांदी ईटीएफ तक

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नवंबर का पहला हफ्ता नए अवसरों से भरा है। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड और क्वांट म्यूचुअल फंड दो नए फंड ऑफर (एनएफओ) लॉन्च करने जा रहे हैं, जो निवेशकों को डेट और चांदी में निवेश के विकल्प मुहैया कराएंगे। ये स्कीमें अलग-अलग जोखिम प्रोफाइल और निवेश लक्ष्यों वाले निवेशकों को आकर्षित करेंगी। कोटक फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान सीरीज 336 कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड 2 से 4 नवंबर तक कोटक फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान सीरीज 336 खोलेगा। यह एक क्लोज्ड-एंड डेट स्कीम है, जिसकी अवधि 125 दिन होगी। यह स्कीम सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड सहित डेट व मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करेगी। इसमें न्यूनतम 5,000 रुपये से निवेश किया जा सकता है और कोई एंट्री या एग्जिट लोड नहीं है। रिस्कोमीटर पर इसे मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में रखा गया है, जो शॉर्ट-टर्म के लिए डेट में सुरक्षित निवेश चाहने वालों के लिए उपयुक्त है। वहीं क्वांट म्यूचुअल फंड 4 से 6 नवंबर तक क्वांट सिल्वर ईटीएफ एफओएफ लॉन्च करेगा। यह एक ओपन-एंडेड फंड ऑफ फंड्स है, जो क्वांट सिल्वर ईटीएफ की यूनिट्स में निवेश करके चांदी की कीमतों का फायदा उठाने का लक्ष्य रखता है। इसमें भी न्यूनतम 5,000 रुपये से शुरुआत की जा सकती है, लेकिन अगर निवेशक यूनिट आवंटन के 15 दिनों के भीतर निकासी करते हैं, तो एक फीसदी एग्जिट लोड लगेगा। इस स्कीम को बहुत अधिक जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है, जो लंबी अवधि के लिए चांदी में निवेश करने और कीमतों में उतार-चढ़ाव सहन करने वाले निवेशकों के लिए है।

कंपनियों पर बढ़ा बोझ, बिक्री का 44 फीसदी हिस्सा खर्च में गया

नई दिल्ली। भारतीय कंपनियों को कच्चे माल की बढ़ती लागत से जूझना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर उनके मुनाफे और अंततः उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है। सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि जून तिमाही में देश की गैर-वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों की प्रत्येक 100 रुपये की बिक्री में से 44 रुपये कच्चे माल और संबंधित खर्चों को पूरा करने में चले गए। यह पिछले लगभग एक दशक में किसी भी तिमाही में दर्ज किया गया सबसे ऊंचा आंकड़ा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ती लागत के दबाव को दर्शाता है। सीएमआईई द्वारा समीक्षा की गई 3,687 गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए जून तिमाही में कच्चे माल, स्टोर्स और स्पेयर पार्ट्स पर खर्च का हिस्सा 44.49 प्रतिशत रहा। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज 38.77 प्रतिशत के आंकड़े से 5.72 प्रतिशत अधिक है। स्टोर्स और स्पेयर पार्ट्स में विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान उपयोग होने वाली सहायक वस्तुएं, जैसे लुब्रिकेंट्स या कलपुर्जे शामिल हैं। यह रुझान सितंबर तिमाही में भी बरकरार रहा, जहां कच्चे माल और उससे जुड़ी लागत कुल बिक्री का लगभग 41 प्रतिशत रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि (39.8 प्रतिशत) से अधिक है। गैर-वित्तीय क्षेत्र में स्टील, ऑटोमोबाइल, खनन और निर्माण जैसी प्रमुख औद्योगिक कंपनियां शामिल हैं। यह तीसरी तिमाही है जिस पर फरवरी में शुरू हुए पश्चिम एशिया संघर्ष का असर पड़ा है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हुई हैं और कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं। हालांकि कंपनियों के पास आमतौर पर कच्चे माल का स्टॉक होता है जो अस्थायी लागत बढ़ोतरी से बचाव कर सकता है, लेकिन यह सुरक्षा सीमित समय के लिए ही होती है। जून के ये उच्च आंकड़े चालू सितंबर तिमाही के आय सत्र के लिए संभावित चुनौतियों का संकेत देते हैं। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार कच्चे माल की बढ़ती लागत कुछ खास क्षेत्रों में मांग को प्रभावित कर सकती है, खासकर उन घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनियों पर जो कीमतें नहीं बढ़ा पाई हैं।

यूपीआई ने रचा इतिहास, दैनिक लेनदेन 1 लाख करोड़ के पार

अक्टूबर में औसत दैनिक लेनदेन भी रिकॉर्ड 82.2 करोड़ रहा



नई दिल्ली। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। अक्टूबर महीने में यूपीआई के जरिए होने वाले लेनदेन का औसत दैनिक मूल्य पहली बार 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया, जो देश में डिजिटल लेनदेन की बढ़ती स्वीकार्यता और क्षमता का एक नया कीर्तिमान है। अक्टूबर 2026 में यूपीआई ने न सिर्फ दैनिक मूल्य में रिकॉर्ड बनाया, बल्कि औसत दैनिक लेनदेन की संख्या भी 82.2 करोड़ तक पहुंच गई, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। इस महीने कुल 25.47 अरब लेनदेन हुए, जो अक्टूबर 2025 में दर्ज किए गए 20.7 अरब लेनदेन की तुलना में लगभग 23 प्रतिशत अधिक हैं। मूल्य के संदर्भ में, अक्टूबर 2026 में 31.53 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन हुए, जो पिछले साल के 27.27 लाख करोड़ रुपये से 16 प्रतिशत अधिक हैं। उद्योग विशेषज्ञों ने इस उल्लेखनीय वृद्धि का श्रेय त्योहारी सीजन को दिया है। नवरात्रि और बड़ी ऑनलाइन बिक्री गतिविधियों ने अक्टूबर में उपभोक्ताओं को रोजमर्रा के भुगतानों के साथ-साथ त्योहारों की खरीदारी के लिए भी यूपीआई का जमकर इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। अप्रैल से अगस्त तक जहां यूपीआई भुगतानों की संख्या बढ़ रही थी, वहीं उनका कुल दैनिक मूल्य स्थिर था और औसत भुगतान राशि कम हो रही थी। हालांकि, सितंबर और अक्टूबर में इस प्रवृत्ति में बदलाव आया, जहां भुगतानों की संख्या की तुलना में उनके मूल्य में तेजी से बढ़ोतरी हुई और लगातार दो महीने औसत भुगतान राशि में इजाफा देखा गया। सितंबर में 29.37 लाख करोड़ रुपये के 24.06 अरब लेनदेन हुए थे, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 29.82 लाख करोड़ रुपये और 24.5 अरब भुगतानों का था। हालांकि, इस वृद्धि के साथ उद्योग जगत के अधिकारियों ने भुगतान प्रणाली की दीर्घकालिक टिकाऊपन पर चिंता जताई है। प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) संरचना, जिसे शुरू में 15 अक्टूबर को लागू किया जाना था, अब खबरों के अनुसार दिवाली के बाद तक टाल दिया गया है। यह देरी भारत के डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे के दीर्घकालिक टिकाऊपन के संबंध में महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि खरीदारी के चरम सीजन में लेनदेन की संख्या बढ़ने के कारण यह जरूरी है कि डिजिटल भुगतान ग्राहकों और व्यापारियों दोनों के लिए किफायती बने रहें, साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि पूरा पारिस्थितिकी तंत्र व्यावसायिक रूप से टिकाऊ बना रहे।

दिवाली पर घरेलू उड़ानों की संख्या में 2.6 फीसदी की कटौती

नई दिल्ली। देश की विमानन कंपनियां दिवाली के त्योहार के दौरान घरेलू उड़ानों की संख्या में 2.6 फीसदी की कटौती करने जा रही हैं। हवाई किराए में बढ़ोतरी और यात्रियों की मांग में कमी के संकेतों के चलते यह फैसला लिया गया है, जिससे त्योहारों पर घर जाने की योजना बना रहे लाखों लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। विमानन आंकड़ों के विश्लेषण से मिली जानकारी के अनुसार, आगामी नवंबर माह में भारतीय एयरलाइंस हर सप्ताह 22,306 उड़ानें संचालित करने का कार्यक्रम है, जो पिछले साल के त्योहारी महीने अक्टूबर में संचालित 22,912 उड़ानों की तुलना में 606 उड़ानें या 2.6 फीसदी कम है। ईंधन की बढ़ती कीमतें और रुपये में कमजोरी के कारण हवाई यात्रा महंगी होने से विमानन कंपनियों ने यह कदम उठाया है, ताकि वे यात्रियों की वास्तविक मांग के हिसाब से उड़ानों का संचालन कर सकें। उड़ानों में सर्वाधिक कटौती एयर इंडिया ने की है, जिसने पिछले साल अक्टूबर की तुलना में इस नवंबर में अपनी साप्ताहिक घरेलू उड़ानों में 14.9 फीसदी (543 उड़ानें) की कमी कर उन्हें 3,101 कर दिया है। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो ने भी 2.7 फीसदी (375 उड़ानें) घटाकर अपनी साप्ताहिक उड़ानों को 13,697 तक सीमित किया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 3.1 फीसदी (78 उड़ानें) और स्पाइसजेट ने 5.2 फीसदी (37 उड़ानें) की कटौती की है। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले मार्गों में हैदराबाद-तिरुपति और दिल्ली-हैदराबाद शामिल हैं, जहां प्रत्येक पर 86-86 साप्ताहिक उड़ानें कम हुई हैं।



नई दिल्ली के रामलीला मैदान में %वोट बचाओ, देश बचाओ रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी सांसद तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के अन्य नेता मौजूद रहे।

रुपया 21 पैसे की गिरावट के साथ 94.97 डॉलर पर खुला

मुंबई। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को रुपया शुरुआती कारोबार में 21 पैसे की गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94.97 पर पहुंच गया। विदेशी बाजारों में अमेरिकी डॉलर की बढ़ती मांग से घरेलू मुद्रा पर दबाव है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि हालांकि घरेलू बाजारों में तेजी और कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी से रुपये को निचले स्तर पर थोड़ा समर्थन मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 94.90 प्रति डॉलर पर खुला। फिर लुढ़ककर 94.97 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 21 पैसे की गिरावट है।

कोल इंडिया की रिकॉर्ड कोयला आपूर्ति, पहली बार 7 करोड़ टन का आंकड़ा पार

नई दिल्ली। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अक्टूबर 2026 में कोयला आपूर्ति के सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए, पहली बार मासिक आपूर्ति 7 करोड़ टन के आंकड़े को पार कर गई। यह उपलब्धि देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने और ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों को दर्शाती है, जिससे ऊर्जा संकट की चिंताओं को दूर करने में मदद मिली है। कंपनी ने अक्टूबर 2026 में कुल 7.03 करोड़ टन कोयले की आपूर्ति की, जो पिछले वित्तीय वर्ष के इसी महीने के मुकाबले 19 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि है। इससे पहले का मासिक रिकॉर्ड मार्च 2026 में 6.94 करोड़ टन था। बिजली क्षेत्र को की गई आपूर्ति भी 5.71 करोड़ टन के अब तक के सर्वाधिक मासिक स्तर पर पहुंच गई, जिसने मई 2024 के पिछले रिकॉर्ड को पछाड़ दिया। यह रिकॉर्ड प्रदर्शन ऐसे समय में सामने आया है, जब हाल ही में देश के कई बिजली संयंत्रों में कोयले के कम स्टॉक को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं। घरेलू उत्पादन में इस वृद्धि के साथ, अगस्त 2026 में देश का कुल कोयला आयात 5.83 प्रतिशत घटकर 10.457 करोड़ टन रह गया।

इंडिया ब्लॉक की रैली से दिल्ली के कारोबारियों को 10 हजार करोड़ का नुकसान

पुरानी और सेंट्रल दिल्ली के 20-25 बाजार हुए प्रभावित, आपूर्ति श्रृंखला पर भी असर

नई दिल्ली। दिवाली से पहले बाजारों में रौनक की उम्मीदों को 1 नवंबर को हुई इंडिया ब्लॉक की रामलीला मैदान रैली से गहरा झटका लगा है। व्यापारी संगठन सीटीआई ने दावा किया है कि इस रैली के चलते पुरानी और सेंट्रल दिल्ली के करीब 20 से 25 बाजारों में कारोबार ठप रहा, जिससे व्यापारियों को लगभग 10,000 से 11,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। सीटीआई के एक अधिकारी के मुताबिक, रामलीला मैदान के आसपास की करीब 3 लाख दुकानों में से लगभग 80 फीसदी यानी 2.5 लाख दुकानें रैली के दिन बंद रहीं। व्यापारियों ने बड़ी संख्या में लोगों और वाहनों की आवाजाही की आशंका के चलते दुकानें बंद रखने का फैसला किया, जिससे ग्राहक भी कम आए। चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावली, कश्मीरी गेट, चावड़ी बाजार, दरियागंज, पहाड़गंज, कनॉट प्लेस सहित कई थोक और खुदरा बाजार पूरी तरह प्रभावित हुए। इन बाजारों से सिर्फ दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी सामान की आपूर्ति होती है। सीटीआई का दावा है कि रोजाना करीब 5,000 ट्रक और टेम्पो की आवाजाही प्रभावित हुई, जिससे त्योहारों से पहले आपूर्ति श्रृंखला में बड़ा व्यवधान आया। व्यापारियों ने रैली से पहले ही दिवाली और धनतेरस के महत्वपूर्ण व्यापारिक समय को देखते हुए चिंता जताई थी। सीटीआई ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित इं?डिया ब्लॉक नेताओं से अपील की थी कि रैली को दिवाली के बाद या बुराड़ी मैदान में आयोजित किया जाए, लेकिन उनकी गुहार अनसुनी कर दी गई।

राष्ट्र भक्ति की अलख जगाता दैनिक
राष्ट्रीय गरिमा
राष्ट्र एक बगीचा है और हम सब इसके माली

भोपाल को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए तत्परता से कार्य करें : संभागायुक्त शर्मा

संभागायुक्त कार्यालय में नगर निगम के अधिकारियों के साथ आवास योजना बैठक की



भोपाल। भोपाल संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि राजधानी को झुग्गी मुक्त बनाने और उनमें रह रहे नगरवासियों को स्वच्छ वातावरण एवं सुविधायुक्त प्रधानमंत्री आवास दिलवाने के लिए अधिकारीगण तत्परतापूर्वक कार्रवाई करें। संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने यह निर्देश सोमवार को संभागायुक्त कार्यालय में नगर निगम के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना संबंधी बैठक में दिए। बैठक में आयुक्त नगर निगम रामप्रकाश अहिरवार,संयुक्त आयुक्त राजस्व डॉ.विनोद यादव,अपर आयुक्त नगर निगम आशीष वशिष्ठ,सीईओ बीडीए श्यामवीर सिंह,अपर कलेक्टर पी.सी शाक्य सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में संभागायुक्त ने नगर निगम के झुग्गी मुक्त भोपाल प्रोजेक्ट पर विस्तार से चर्चा की। निगम आयुक्त द्वारा झुग्गी मुक्त भोपाल की प्रस्तावित कार्य योजना का विस्तृत प्रजेन्टेशन संभाग आयुक्त के समक्ष दिया। बैठक में बताया गया कि झुग्गी मुक्त भोपाल प्रोजेक्ट के अंतर्गत वल्लभ भवन पहाड़ी,अरेरा हिल्स,एम.पी.नगर,बाणगंगा क्षेत्र,पत्रकार कॉलोनी,मैनिट और कोलार तिराहा आदि क्षेत्रों को झुग्गी मुक्त किए जाने की योजना है। इसके लिए दानापानी सब्जी फार्म,राजीव नगर,अर्जुन नगर आदि क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने की योजना है, जिनमे झुग्गीवासियों को विस्थापित किया जाएगा। पहले आवास निर्माण का कार्य किए जाना है,इसके बाद विस्थापन की कार्रवाई होगी। दानापानी फे-1 के अंतर्गत 7560 ई.डब्ल्यू.एस आवास बनाए जाने की योजना है। संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने ने संभागायुक्त कार्यालय में सोमवार को भोपाल शहर एवं संभाग के सभी जिलों की सड़कों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के सम्बन्ध में सड़क निर्माण एजेंसियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि भोपाल शहर के सभी रोड तक दीपावली तक गड्ढा मुक्त करें एवं रिंग रोड की मरम्मत की जाए। इसके साथ ही ब्लेक स्पॉट फ्री एवं चौराहों को लेफ्ट टर्न फ्री बनाने के निर्देश भी दिए गए। संभागायुक्त ने बैठक में भोपाल शहर एवं आस-पास की सड़कों को दीवाली के पूर्व मरम्मत कार्य कर गड्ढा मुक्त करने एवं ब्लैक स्पॉट दूर करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में शहर के सभी मार्गों के रोड रेस्टोरेंशन का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में भोपाल शहर के आसपास के राष्ट्रीय राज्य मार्गों में मेंटेनेंस का कार्य 15 नवंबर तक पूर्ण करने तथा इज्तिमा की तैयारियों को लेकर शहर के चारों तरफ के मार्गों का कार्य 20 नवंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इज्तिमा स्थल के लिए पहुँच मार्ग के कार्यों को तय समय में पूर्ण करें। संभागायुक्त ने कहा कि आगामी जनवरी माह में भोपाल में जीआईएस प्रस्तावित है। उन्होंने भोपाल के आसपास सांची,भोजपुर जैसे पर्यटन स्थलों की सड़कों पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए। मेट्रो के निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कें सुधारने में तत्परता बरतने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि समग्र रूप से यह सुनिश्चित करें कि सड़कें बेहतर हों और आम जनता को परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री ने स्थापना दिवस प्रदर्शनी में आधुनिक तकनीकों का किया अवलोकन

भोपाल। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को भोपाल में आयोजित तीन दिवसीय उद्यानिकी एवं कृषि प्रदर्शनी में जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड ने आधुनिक उद्यानिकी एवं कृषि तकनीकों एवं उत्पादों का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्टॉल पर ऑटोमेशन, ड्रिप इरिगेशन, पीवीसी उत्पाद,हाईटेक टिश्यू कल्चर पौधे तथा विभिन्न बागवानी फसलों की उन्नत पौध प्रदर्शित सामग्री का अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ.यादव को विशेष रूप से लहसुन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, टिश्यू कल्चर केले,आम एवं मौसंबी की उन्नत पौध सामग्री तथा हरदा-नर्मदापुरम क्षेत्र में बागवानी विस्तार की योजनाओं से अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने लहसुन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सराहना की इससे किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। कंपनी के स्टेट हेड वी. वी. डांगरिकर ने अतिथियों को मध्य प्रदेश में कंपनी द्वारा किए जा रहे कृषि एवं उद्यानिकी विकास कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में पंकज जायसवाल, एग्रोनॉमिस्ट अजहर जैदी, इंजीनियर प्रांजु सूर्यवंशी एवं शुभम गोयल का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

भाजपा कार्यालय में मंत्री गौतम टेटवाल ने सुनीं कार्यकर्ताओं की समस्या

भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री गौतम टेटवाल ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने। इस दौरान उन्होंने जनसमस्याओं के निराकरण को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिन मामलों में विभागीय स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता है,उन्हें शीघ्र समाधान के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। मंत्री टेटवाल ने कार्यकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों और समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनके निराकरण के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से सामने आने वाली जनसमस्याओं का परीक्षण कर उनके समाधान का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान करना और उन्हें शासन की योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ दिलाना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में संगठन भी इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। सरकार और संगठन का उद्देश्य है कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण हो और पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे।

अंतर्राज्यीय स्तर पर तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

भोपाल। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, क्षेत्रीय इकाई इंदौर ने काले हिरण एवं चिंकारा का शिकार कर अंतर्राज्यीय स्तर पर तस्करी करने वाले संगठित गिरोह के आरोपी रिजवान की जमानत याचिका उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा 29 अक्टूबर, 2026 को खारिज कर दी। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स क्षेत्रीय इकाई इंदौर ने वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम के तहत एक बड़ी कानूनी सफलता हासिल की है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य-जीव के दिशा-निर्देश में एसटीएफ इकाई इंदौर, स्थानीय पुलिस और वन मण्डल इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में किशनगंज इंदौर क्षेत्र में एक विशेष कार्रवाई की गई थी। इस दौरान लगभग 65 किलोग्राम वन्य-जीव मांस, एक देशी पिस्टल, 3 जीवित कारतूस तथा तस्करी में प्रयुक्त टोयोटा इनोवा क्रिस्टा वाहन जप्त कर 3 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। इस संदर्भ में वन मण्डल इंदौर द्वारा भारतीय वन अधिनियम-1927 एवं वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम-1972 के प्रावधानों के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण 3 दिसम्बर, 2024 को दर्ज किया गया था। प्रकरण की संवेदनशीलता और गिरोह के नेटवर्क को देखते हुए अग्रिम विवेचना का दायित्व स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इंदौर को सौंपा गया था।

वन विभाग की सतर्कता से टला वन्यप्राणी का शिकार,एक गिरफ्तार

भोपाल। मध्य प्रदेश में वन्यप्राणियों के अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग द्वारा लगातार निगरानी एवं गश्ती की जा रही है। इसी क्रम में वनमण्डल दक्षिण शहडोल की रात्रि गश्ती टीम ने तत्परता दिखाते हुए विद्युत करंट से वन्यप्राणी का शिकार करने की कोशिश को नाकाम कर दिया। मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जिला जेल शहडोल भेज दिया गया है। जनसंपर्क अधिकारी के.के. जोशी ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल महेन्द्र प्रताप सिंह (भा.व.से.) के निर्देशन तथा वनमण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल श्रद्धा पन्द्रे (भा.व.से.) एवं उप वनमण्डलाधिकारी सोहागपुर संतोष कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में 30 एवं 31 अक्टूबर 2026 की दरमियानी रात वनमण्डल दक्षिण शहडोल के अंतर्गत गठित रात्रि गश्ती दल वन क्षेत्र में निगरानी कर रहा था। इसी दौरान ग्राम धनगवां के भैरव टोला राजस्व क्षेत्र में भैरव टोला से कॉलोनी की ओर जाने वाली 11 केवी विद्युत लाइन से वन्यप्राणियों के शिकार के लिए करंट फैलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही गश्ती दल ने तत्काल मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान घटनास्थल से कुछ व्यक्ति भागते हुए दिखाई दिए। गश्ती दल ने तत्परता दिखाते हुए एक व्यक्ति को पकड़ लिया।

पुलिसकर्मियों एवं उनके परिवारों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता: डीजीपी

राज्यस्तरीय संयुक्त पुलिस परामर्शदात्री पुलिस कल्याण समिति की बैठक संपन्न



भोपाल। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाणा ने कहा कि पुलिस एक अनुशासित वर्दीधारी संगठन है। इसकी कार्यक्षमता और मनोबल बनाए रखने के लिए अनुशासन के साथ पुलिसकर्मियों एवं उनके परिवारों के कल्याण पर ध्यान देना भी आवश्यक है। पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य, पारिवारिक संतुष्टि और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े विषयों का समय पर समाधान संगठन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। डीजीपी मकवाणा सोमवार को पुलिसकर्मियों एवं उनके परिवारों के कल्याण, सेवा सुविधाओं और कार्य परिस्थितियों में निरंतर सुधार के उद्देश्य से आयोजित राज्य संयुक्त पुलिस परामर्शदात्री समिति एवं पुलिस कल्याण समिति की वार्षिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित बैठक में पुलिसकर्मियों एवं उनके परिवारों से जुड़े विभिन्न कल्याणकारी विषयों पर विचार-विमर्श किया गया तथा आवश्यक निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत देवास जिले के खातेगांव थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप पुरी के कर्तव्य निर्वहन के दौरान गत रात्रि हुए आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त कर की गई। उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत अधिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बैठक में डीजीपी मकवाणा ने ने बताया कि पिछली बैठक में लिए गए अधिकांश निर्णयों का क्रियान्वयन किया जा चुका है। उन्होंने इकाई प्रमुखों को निर्देश दिए कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र पुलिसकर्मियों एवं उनके परिवारों तक समय पर पहुंचे और योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने सभी इकाई प्रमुखों को नियमित जनसुनवाई आयोजित करने, शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करने तथा आम नागरिकों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील एवं अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आकस्मिक परिस्थितियों में पुलिसकर्मियों के आश्रित परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने में अनावश्यक दस्तावेजी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। बीमा दावों एवं अन्य लाभों से संबंधित मामलों की इकाई स्तर पर नियमित निगरानी करते हुए परिवारों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण विषय बताते हुए कहा कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को गंभीरता से समझकर संस्थागत स्तर पर समाधान के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केंद्र के प्रस्ताव की सराहना की। साथ ही हार्टफुलनेस संस्था के सहयोग से संचालित ध्यान एवं मानसिक स्वास्थ्य सत्रों की नियमित समीक्षा तथा योग, आसन एवं प्राणायाम जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। डीजीपी मकवाणा ने दिशा लर्निंग सेंटर की उपयोगिता बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि इन केंद्रों को केवल पुस्तकालय तक सीमित न रखते हुए पुलिस परिवारों के बच्चों की वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया जाए।

सहस्त्रदीप महोत्सव में लिया जाएगा एक दीप के साथ एक सामाजिक संकल्प

आगामी 14 नवंबर को 10 हजार दीपों से जगमगाएगा भोपाल शहर

भोपाल। भगवान राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आगामी 14 नवंबर 2026, शनिवार को भोपाल में भव्य सहस्त्रदीप महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम शाम 6 बजे से प्रभु इच्छा तक सहस्त्रबाहु ब्रिज,जेके अस्पताल (एलएनसीटी विश्वविद्यालय) परिसर के सामने,कोलार रोड, भोपाल में आयोजित होगा। इस वर्ष आयोजन को केवल एक धार्मिक कार्यक्रम तक सीमित न रखते हुए इसे कलचुरी समाज की एकता, संस्कार, सेवा और सामाजिक संकल्प का जन-अभियान बनाने की तैयारी की जा रही है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज के अधिक से अधिक परिवारों,युवाओं,महिलाओं,सामाजिक संगठनों और समाजसेवियों को एक मंच पर जोड़ना है। आयोजन समिति ने इस वर्ष 10,000 दीप प्रज्वलित करने, 1,000 परिवारों को जोड़ने,100 युवाओं को अभियान से जोड़ने तथा 100 सामाजिक संकल्पों को जनभागीदारी के माध्यम से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अभियान के तहत एक परिवार-एक दीप का संदेश घर-घर पहुंचाया जाएगा। समाजबंधुओं से आग्रह किया जाएगा कि वे अपने परिवार के साथ कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान सहस्त्रबाहु के नाम एक दीप प्रज्वलित करें और समाजहित में एक सकारात्मक संकल्प लें। आयोजन समिति के अनुसार कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहयोग की व्यवस्था रखी गई है,लेकिन किसी भी व्यक्ति की सहभागिता को आर्थिक सहयोग से नहीं जोड़ा जाएगा। बिना आर्थिक सहयोग के भी परिवार,युवा,समाजसेवी और सामाजिक संगठन इस अभियान का हिस्सा बन सकेंगे। आयोजन को व्यापक जनभागीदारी देने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों से संपर्क किया जाएगा तथा युवाओं को सहस्त्रदीप युवा दूत के रूप में अभियान से जोड़ा जाएगा। सहस्त्रदीप महोत्सव की एक विशेष पहल के रूप में लोगों को दीप के साथ सामाजिक संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शिक्षा, रक्तदान, नशामुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, जरूरतमंदों की सहायता और समाजसेवा जैसे विषयों पर समाजबंधु अपने व्यक्तिगत संकल्प दर्ज करा सकेंगे।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो ने महापौर श्रीमती मालती राय की उपस्थिति में पी.एम.स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से किया संवाद



राष्ट्रीय गरिमा समाचार भोपाल। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो ने महापौर श्रीमती मालती राय की उपस्थिति में पी.एम.स्वनिधि योजना के लाभार्थी पथ विक्रेताओं से संवाद किया। निगम मुख्यालय अटल भवन के सभाकक्ष में सोमवार को आहूत समन्वय बैठक में निगम अधिकारी एवं बड़ी संख्या में पी.एम.स्वनिधि के लाभार्थी पथ विक्रेता मौजूद थे।

अवैध शराब के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा : मंत्री सारंग

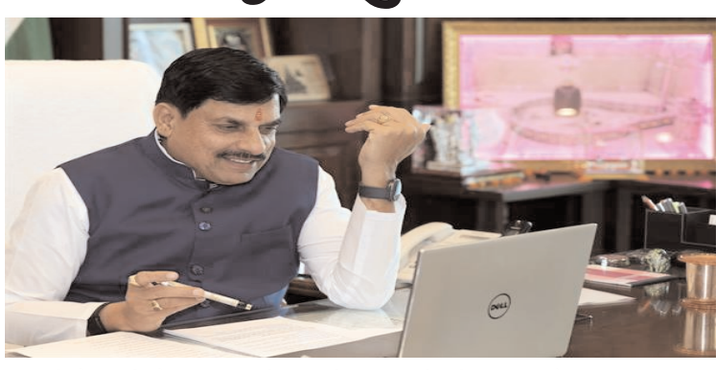


देवास शराब कांड में कांग्रेस नेताओं का नाम सामने आने के बाद मंत्री सारंग ने उठाए सवाल

भोपाल। मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव में अवैध शराब तस्करी के मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इस प्रकरण में कांग्रेस नेताओं के नाम सामने आने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से जवाब मांगा है। उन्होंने सवाल उठाया कि शराब तस्करी के मामलों में बार-बार कांग्रेस नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के नाम क्यों सामने आ रहे हैं? क्या अवैध शराब कारोबार से होने वाली कमाई का इस्तेमाल कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य खर्चों में किया जा रहा है? मंत्री सारंग ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि खातेगांव में सामने आए मामले के प्रारंभिक तथ्यों के अनुसार, इसके तार हरदा के युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रभारी राहुल जायसवाल से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि टिमरनी की जिस शराब दुकान का नाम इस प्रकरण में सामने आया है, उसमें राहुल जायसवाल और उनके भाई मनीष जायसवाल की साझेदारी है। दुकान के मैनेजर भूपेंद्र राणा ने भी पुलिस को इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हालांकि, मामले में संबंधित लोगों की भूमिका की जांच जारी है। सारंग ने कहा कि इससे पहले देवास के एक अवैध शराब प्रकरण में कांग्रेस प्रवक्ता आनंद कासलीवाल के पुत्र अमन कासलीवाल का नाम सामने आया था। अब खातेगांव के मामले में राहुल जायसवाल और उनके भाई की कथित साझेदारी वाली शराब दुकान का उल्लेख जांच में हो रहा है। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों में कांग्रेस नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के नाम आने पर पार्टी नेतृत्व को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से सवाल किया कि आखिर अवैध शराब के कारोबार में कांग्रेस से जुड़े लोगों के नाम बार-बार क्यों सामने आ रहे हैं? इस नेटवर्क को किसका संरक्षण प्राप्त है और इसकी कमाई का इस्तेमाल कहां हो रहा है? सारंग ने यह भी पूछा कि कहीं अवैध कमाई से कांग्रेस के बिजली बिल, धरना-प्रदर्शनों और राजनीतिक गतिविधियों का खर्च तो नहीं चलाया जा रहा है।

किसानों की आय में वृद्धि और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव

सिवनी में हुए बलराम कृषि महोत्सव में वर्चुअली शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव



भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण, उनकी आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने, कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहित करने तथा कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ.यादव सोमवार को मंत्रालय से सिवनी जिले की सिमरिया मंडी प्रांगण में हुए बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने किसानों से जो वादा किया था, उसे पूरा भी किया। इन दिनों प्रदेश में किसानों को खेती-किसानी के कामों के लिए दिन में 10 घंटे बिजली दी जा रही है। रबी फसलों की सिंचाई के लिए दिन के समय 10 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति से किसानों को रात में सिंचाई की मजबूरी से राहत मिलेगी। उन्होंने धान उपार्जन का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों की सुविधा और अधिकाधिक पात्र किसानों को समर्थन मूल्य पर उपज विक्रय का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धान उपार्जन के पंजीयन की अंतिम तिथि 4 नवंबर तक बढ़ाई गई है। कोई भी पात्र किसान पंजीयन से वंचित न रहे,इस दिशा में आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले का जीराशंकर चॉवल अपनी विशिष्ट सुगंध और स्वाद के कारण अलग पहचान रखता है। बड़े आकार और मिठास से भरपूर सिवनी का जंबो सीताफल भी जिले की विशेष पहचान बन रहा है। जिले में टमाटर,मिर्च,अलसी, सरसों और सूरजमुखी जैसी फसलों की खेती भी किसानों के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन होने से किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिले, इसी उद्देश्य से सिवनी में शीघ्र ही फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। इससे कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर विकसित होंगे।

ट्रांसमिशन लाइनों के प्रतिबंधित कॉरिडोर में निर्माण करने वाले 853 नोटिस जारी

विद्युत सुरक्षा को लेकर भोपाल में एमपी ट्रांसको चलाएगा जागरूकता अभियान

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अति उच्च दाब (ईएचटी) ट्रांसमिशन लाइनों के प्रतिबंधित कॉरिडोर में हो रहे निर्माण पर नोटिस जारी किये गए हैं। शहर की तीन प्रमुख 132 केवी ट्रांसमिशन लाइनों के राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) क्षेत्र में सामने आए मानव जीवन के लिये खतरा बने निर्माणों के संबंध में अब तक 853 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। यह जानकारी सोमवार को मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी(एमपी ट्रांसको) भोपाल के अधीक्षण अभियंता सुधीर नेमा ने दी। उन्होंने बताया कि बताया कि एमपी ट्रांसको ने इन निर्माणों से संभावित विद्युत दुर्घटनाओं को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाने और संबंधित निर्माणकर्ताओं को सुरक्षा मानकों की जानकारी देने की तैयारी की है। अधीक्षण अभियंता नेमा ने बताया कि भोपाल में जिन तीन 132 केवी ट्रांसमिशन लाइनों के आरओडब्ल्यू क्षेत्र में निर्माण के मामले सामने आए हैं, उनमें गोविंदपुरा भोपाल-बैरागढ़ टैप लालघाटी, भोपाल-आईटी पार्क और भोपाल-अमरावतखुर्द ट्रांसमिशन लाइन शामिल हैं। इन लाइनों के आसपास विभिन्न स्थानों पर निर्माण होने से निर्धारित विद्युत क्लियरेंस बनाए रखने की चुनौती सामने आई है। उन्होंने बताया कि भोपाल में गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र, करोंद, नारियलखेड़ा, देवकीनंदन नगर, बैरागढ़, आनंद नगर, जैन कॉलोनी कलियासोत,रतनपुरऔर आसपास के क्षेत्रों में ट्रांसमिशन लाइनों के नजदीक तेजी से शहरी विस्तार हुआ है। यहां पर ट्रांसमिशन लाइन के प्रतिबंधित कारीडोर में नियम विरुद्ध निर्माण कर लिए गए हैं। कंपनी संबंधित निर्माणकर्ताओं को विद्युत सुरक्षा प्रावधानों की जानकारी देने के साथ स्थानीय प्रशासन के सहयोग से जागरूकता अभियान भी चलाएगी। संभावित विद्युत दुर्घटनाओं और व्यवधानों की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।